SOUVENIR

CUM ABSTRACT BOOK

National Conference

on

"Government Educational Institutions:
Current Scenario and Challenges"

March 24-25, 2023

Organized by

GUHAR

Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860, Delhi
Registration No. S/3249/SDM/NW/2018

In Collaboration with

Digambar Jain College
Baraut (Baghpat), Uttar Pradesh

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन

विषय

सरकारी शैक्षिक संस्थानः वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

24-25 मार्च, 2023

आयोजक

गुहार

सहयोगी

दिगम्बर जैन महाविद्यालय

(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से संबद्ध)

संरक्षक

डॉ. वीरेंद्र सिंह

प्राचार्य, दिगम्बर जैन महाविद्यालय,
बड़ौत (बागपत)

संयोजक

श्री दीपक कुमार

अध्यक्ष, गुहार

सह–संयोजक

डॉ. किरन गर्ग

सहायक प्राध्यापिका
दिगम्बर जैन महाविद्यालय, बड़ौत (बागपत)

कार्यकारी आयोजन समिति

डॉ. दीपक जैन
सहायक प्राध्यापक
दिगम्बर जैन महाविद्यालय, बड़ौत

डॉ. रविन्द्र कुमार
सहायक प्राध्यापक
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

डॉ. राहुल चिमूरकर
सहायक प्राध्यापक, देशबंधु कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. रोहित भारती
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

श्री दिव्यांशु शंगारी
सदस्य, गुहार

श्री देवराज चौहान
सदस्य, गुहार

Published by

GUHAR

Registered Under Societiesa registration act XXI of 1860
Registration No.: S/3249/SDM/NW/2018
NITI Aayog Unique ID: DL/2018/0210085
Address: 19/5, Street No. 2, A-1 Block, Sant Nagar Extension, Burari, Delhi, 110084
Phone: +91 95609-31074
E-mail: guhar.ngo@gmail.com, info@guhar.org
Website: www.guhar.org

सम्पादकीय

प्रिय पाठकों,

गुहार की तरफ से आप सभी का विनम्र अभिवादन,

दिगंबर जैन कॉलेज, बडौत में गुहार द्वारा आयोजित "सरकारी शिक्षण संस्थानः वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ" विषय पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करते हुए आप सभी विद्वानजनों का स्वागत करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य और बड़े सम्मान की बात है। इस शुभ अवसर पर यह स्मारिका एवं शोध सारांश पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है।

सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए देश के 13 से अधिक राज्यों से शिक्षाविदों के 70 से अधिक शोध–पत्र प्राप्त हुए है, जो सम्मेलन के मूल विषय और उप–विषयों से संबंधित है। सम्मेलन को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों में संचालित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान विषयगत क्षेत्रों के व्यावहारिक आयामों पर सुनियोजित ढंग से विचार विमर्श होगा जिससे युवा एवं नवोदित शिक्षक उत्साहित, उर्जावान महसूस करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करेंगे। सम्मेलन में वरिष्ठ विद्वानों के विचार और मार्गदर्शन हम सभी के लिए सकारात्मक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित होगा।

सम्मेलन की योजना बनाने में कई महीनों का प्रयास रहा तथा साथ ही साथ गुहार के सभी सदस्यों एवं दिगंबर जैन कॉलेज के प्राचार्य महोदय से भरपूर सहयोग मिला। अंत में, मैं उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने किसी न किसी रूप में इस सम्मेलन को साकार करने के लिए अपना योगदान दिया है।

मैं उन सभी प्रतिभागियों और विद्वानों का स्वागत करता हूँ जो इस मंच पर अपने अकादमिक विचारों को साझा करने आए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सम्मेलन सभी के लिए सार्थक एवं फलप्रद होगा। हम सभी यहां एक दूसरे से सीखने और प्रगति करने के लिए आए हैं। कृपया एक दूसरे के साथ बातचीत करें, संवाद करें और वक्ताओं से प्रश्न पूछें एवं सम्मेलन का आनंद लें।

दीपक कुमार
संयोजक
अध्यक्ष (गुहार)

गुहार का परिचय

'गुहार' (Global Upliftment of Human Advocacy & Rights) एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना अगस्त, 2018 में हुई थी। यह संस्था समतामूलक समाज के निर्माण में प्रतिबद्ध व्यक्तियों का एक समूह है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रचलित असमानता को समाप्त करना, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करवाना एवं प्रगतिशील समाज की ओर निरंतर अग्रसर रहना है। गुहार का कार्य क्षमता निर्माण, ज्ञान निर्माण और नीति समर्थन के माध्यम से वंचितों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। गुहार द्वारा 'लोकतंत्र को सभी के लिए काम करने' के समग्र परिप्रेक्ष्य में पहल की जा रही है। गुहार न्याय, स्वतंत्रता, शांति और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2 अक्तूबर, 2018 में 'गुहार' द्वारा शिक्षा परियोजना "नई तालीम" को गाँव लुहारी, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। वर्तमान तक 'गुहार' द्वारा तीन केन्द्रों में 600 से अधिक छात्रों लाभान्वित हो चुके है। गुहार द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न विषयों पर सेमीनार/वेबिनार का आयोजन अनेक शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए अभिप्रेरण एवं काउन्सलिंग कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों आदि का आयोजन किया जाता रहा है।

दिगम्बर जैन कॉलिज का परिचय

बड़ौत नगर में 20 जनवरी, 1916 को कुछ प्रबुद्ध दिगम्बर जैन दानवीर एवं यशस्वी मनीषियों द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की आधारशिला रखी गई, वह आज दिगम्बर जैन महाविद्यालय (चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) के रूप में प्रतिष्ठित है। 1947 में महाविद्यालय में स्नातक और 1960 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गयी। इस संस्था के संस्थापकों का मानना था कि यदि युवा मस्तिष्क को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी अहसास कराया जाए तो यह देश सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसके लिए छात्रों की अपने अध्ययन के दौरान कक्षा आधारित शिक्षा के साथ अतिरिक्त गतिविधियों में भी भागीदारी होनी चाहिए।

वर्तमान में महाविद्यालय में 16 विभाग है, जिनमें 10 विभाग स्नातकोत्तर (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित) तथा 6 विभाग स्नातक (वाणिज्य, सांख्यिकी, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, चित्रकला तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद) है। संस्था में छात्र–छात्राओं के लिए एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर्स, रेंजर्स की अनेक इकाइयों के अतिरिक्त खेलकूद विभाग में भारत्तोलन, शक्तित्तोलन, शरीर सौष्ठव, शूटिंग आदि के अतिरिक्त अनेक इंडोर एवं आउटडोर खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा है, जिनका लाभ लेकर संस्था के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर संस्था का गौरव बढ़ाते रहे है।

सम्मेलन की पृष्ठभूमि

शिक्षा मानव समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में समय–समय पर अनेक गठित आयोगों द्वारा शिक्षा के दोषों का उल्लेख किए जाने के उपरान्त भी स्थिति में आशानुरूप परिवर्तन नहीं हो सका है। भारत की वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य भारत की नई शिक्षा प्रणाली की दृष्टि को रेखांकित करने वाले स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान दोनों हैं। NEP 2020 के माध्यम से, भारत सरकार ने हमारे देश की स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी और गतिशील सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। नीति की परिकल्पना है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को छात्रों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना, अपने देश के

साथ संबंध और बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत जागरूकता विकसित करनी चाहिए।

सम्मेलन का महत्व

वर्तमान में भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। हालांकि, भारत को विकसित देश और सुपर पावर बनने के लिए यह जरूरी है कि इस लोकतांत्रिक लाभांश (हमारे देश की युवा पीढ़ी) को तकनीकी कौशल के साथ सही दिशा, सही दृष्टिकोण और सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों एवं आत्मविश्वास के साथ तैयार किया जाए। इसी सन्दर्भ में देश के सर्वांगीण एवं बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है एवं अच्छी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की।

हममें से बहुत से लोग शिक्षक के रूप में या शिक्षकों के साथ अनेक तरह से अनेक मंचों पर काम करते रहे हैं। इन सभी अनुभवों को व्यवस्थित करने की और एक–दूसरे के साथ साझा करने की जरूरत है। दो दिवसीय के इस सम्मेलन का उद्देश्य इन्हीं सवालों पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करना है। इस विचार–विमर्श में शिक्षा से सीधे जुड़े अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें इसके लिए आवश्यक है कि जहाँ तक संभव हो इस संवाद को हम राजकीय भाषा हिन्दी में ही प्रेषित करने का प्रयास करें।

सम्मेलन के उप–विषय

इस सम्मेलन के विषय को हम विभिन्न प्रकरणों में बाँटकर देख सकते हैं और इन पर क्रमिक ढंग से विचार करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं:

- नई शिक्षा नीति 2020।
- शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग।
- शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी।
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सरकारी शिक्षा में चुनौतियाँ एवं समाधान।
- शिक्षक स्वायत्तता (Autonomy) बनाम उत्तरदायित्व (Accountability)।
- शिक्षा आयोग और उनकी संस्तुतियों (Report) के प्रभाव का विश्लेषण।
- स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था (गाँधीजी, टैगोर, विवेकानन्द, विनोबा भावे आदि)।
- शिक्षा में दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण व व्यक्तित्व–निर्माण केन्द्रित शिक्षा।
- शिक्षा का व्यापारीकरण: शिक्षा की गुणवत्ता में पतन?
- शिक्षा में राजनीति : प्राथमिक से उच्च शिक्षा।
- शिक्षण, ज्ञान, कौशल और क्षमता के मानक।
- शिक्षा नेतृत्व, पाठ्यक्रम विकास और प्रभावी शिक्षाशास्त्र के लिए शोध।
- शिक्षा से सम्बंधित अन्य किसी भी विषय पर।

परामर्श मण्डल

- **प्रो सोमदेव शतांशु**, माननीय कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड।
- **डॉ. रणपाल सिंह**, माननीय कुलपति, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय, जींद, हरियाणा।
- **प्रो. करम तेज सिंह सराव**, माननीय प्रतिकुलाधिपति, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, बौद्ध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- **प्रो. उमा शंकर पाण्डेय**, प्राचार्य, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एवं ओएसडी, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- **प्रो. नरेंद्र सिंह,** प्राचार्य, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- **प्रो. राम शर्मा**, प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया, उत्तर प्रदेश।
- **श्री कविन्द्र तालियान**, सीईओ, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, सदस्य– संचालन समिति, संचार मंत्रालय, भारत सरकार।
- **प्रो. पवनेश कुमार**, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन विज्ञान विभाग पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।
- **प्रो. हेमवती नंदन**, प्राध्यापक, भौतिक विज्ञान विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड।
- **प्रो. विनय कुमार**, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, अनुग्रह नारायण कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।
- **डॉ आनंद प्रताप सिंह**, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, (उत्तर प्रदेश)।
- **डॉ. ओमपाल सिंह** (राष्ट्रपति पुरस्कृत) पूर्व प्राचार्य– सनातन धर्म इन्टर कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सदस्य. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
- **डॉ. राजपाल भुल्लर**, सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, डी. ए. वी. कॉलेज, नन्यौला, अम्बाला, हरियाणा।
- **डॉ. शिन्जिता अग्रवाल**, सह-प्राध्यापक, सांख्यिकी विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत, उत्तर प्रदेश।
- **डॉ. सुनीता**, सह-प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत, उत्तर प्रदेश।
- **डॉ. विनय कुमार**, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य विभाग, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू-कश्मीर।
- **डॉ. संदीप कौशिक**, सहायक प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान विभाग, इन्द्रा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।
- **डॉ. विनोद कुमार**, सहायक प्राध्यापक, रसायन विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- **श्री शुधांशु सिंह**, प्रिंसिपल कंसलटेंट, फीडबैक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा।
- **श्री विकास मालिक**, प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, इदरीशपुर, बागपत एवं बेसिक शिक्षा जिलाअध्यक्ष, बागपत, उत्तर प्रदेश।

गुहार कार्यकारिणी सदस्यः **श्री लवकेश** (सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया), **श्री नितांशु अदलखा** (सिंडिकेट बैंक), **श्री प्रदीप कुमार सोहगौरा** (फूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया), **श्री कौस्तुभ मणि सिंह** (समाज सेवी), **श्री सुरजीत गोगोई** (शिक्षक), **शुश्री ज्योति द्विवेदी** (शिक्षिका), एवं **श्रीमती मनीषा विश्नोई** (शिक्षिका)।

Dr. SATYA PAL SINGH
Member of Parliament
(Lok Sabha) Baghpat, Uttar Pradesh
CHAIRPERSON
Joint Committee on Offices of Profit

सत्यमेव जयते

218, Block 'B'
Parliament House Annexe Extensic
New Delhi-110 001
Phone : 011-23035739, 21410293
Fax : 011-21410294

No.73/2019-20/
March 07, 2020

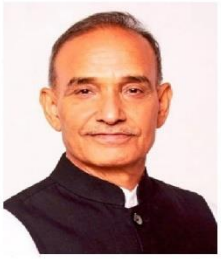

Message

It gives me immense pleasure to note that one of the leading educational institution in our region which is doing exemplary work in the field of education, the Digambar Jain College, Baraut, District Baghpat, Uttar Pradesh; in collaboration with GUHAR (Global Upliftment of Human Advocacy and Rights), is organizing a National Conference on "Government Educational Institutions: Current Scenario and Challenges" at the Mahavira Hall, Digambar Jain College, Baraut, Baghpat on 21st-22nd March 2020. I am given to understand that eminent scholars, academicians, and students from various schools, colleges and universities across the country shall be participating in the Conference. I hope that the proposed Conference shall provide a platform to share experience, knowledge and findings to ensure the development of all sections of our society. I appreciate the efforts put in by Digambar Jain College and GUHAR.

I extend my best wishes to the participants and organizers of the conference for a grand success.

7/3/2020
(Dr. Satya Pal Singh)

Residence: 9, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi-110 001 • Phone: 011-23015800, 07534006112 (M)

नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा
मानित विश्वविद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda
Deemed to be University, Ministry of Culture, Government of India

Tel: +91 6112-281820, +91 8114 599 899 **Fax:** 06112-281505 **E- mail:** vc@nnm.ac.in **Website:** www.nnm.ac.in

प्रो0 वैद्यनाथ लाभ
कुलपति
Prof. Baidyanath Labh
Vice - Chancellor

Dated: March 9, 2020

Message

It is a matter of pleasure that Global upliftment of Human Advocacy and Right in collaboration with Digambar Jain College, Baraut (Baghpat), Uttar Pradesh is organizing a two-day National Conference on the Theme 'Government Educational Institution: Current Scenario and Challenges' on March 21-22, 2020.

There are number of contemporary issues pertaining to educational policies, challenges in strengthening of governmental institutions, ensuring inclusive education etc. which could prepare a solid background for better social understanding and harmony keeping aside caste and religious identities.

The organizers are going to publish a souvenir of abstracts and few related articles covering the focal theme. I congratulate the organizers for this novel venture are with them for a very active, enthusiastic and meaningful conference.

'Sabbe sattā bhavantu sukhitattā'.

(B. Labh)

नालन्दा - ८०३ १११ (बिहार)
NALANDA - 803 111 (BIHAR)

॥ ओ३म् ॥

॥ श्रद्धयाग्निः समिध्यते ॥ (ऋ० १०.१५१.१)

गुरुकुल काङ्गड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Deemed to be University U/s 3 of UGC Act. 1956)

प्रो० सोमदेव शतांशु
कुलपति (कार्यवाहक)

Prof. Somdev Shatanshu
Vice-Chancellor (Officiating)

क्रमाङ्क/Ref. No. 1-2/VCO/EC/

दिनाङ्क/Date 16.03.2023

MESSAGE

I am delighted to bring this message to the **National Conference on the theme "Government Educational Institutions: Current Scenario and Challenges" organized by Digambar Jain College, Baraut, Baghpat (U.P.)** from 24th March, 2023 to 25th March, 2023.

I hope this conference will allow the participants a productive dialog in aspiring for excellence in the field of education. Some of the underlying issues will be covered in depth at the conference by Guest Speakers. I extend my heartfelt appreciation to them.

I add my best wishes for successful and fruitful deliberations.

(Prof. Somdev Shatanshu)
Vice-Chancellor

पो०ऑ०-गुरुकुल काङ्गड़ी, हरिद्वार-249404, उत्तराखण्ड (भारत) | P.O. Gurukula Kangri, Haridwar-249404, Uttarakhand (INDIA)
Tel.: +91-7300761329 (O), E-Mail: vcoffice@gkv.ac.in, somdev@gkv.ac.in Website: www.gkv.ac.in

☎ Office : 01234-292011
Fax : 01234-262060

दिगम्बर जैन कॉलिज

NAAC Accredited 'B' Grade Institutions
(अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था)
बड़ौत-250611 (बागपत) उ०प्र०

प्रो० वीरेन्द्र सिंह,
प्राचार्य

– संदेश –

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रहीं है कि "गुहार" द्वारा हमारे महाविद्यालय दिगम्बर जैन कॉलिज, बड़ौत (बागपत), उत्तर प्रदेश में "सरकारी शिक्षण संस्था : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियॉं" विषय पर 21–22 मार्च 2020 को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन शिक्षा की विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उनकी विस्तृत व्याख्या करके समाधान हेतु शैक्षिक सुझाव प्रस्तुत करेगा। वस्तुतः वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में नित नवीन परिवर्तन हो रहे है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे अधिक प्रभावित हुई है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन से शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगें।

मैं इस शुभ अवसर पर सम्मेलन की गरिमा बढ़ाने वाले आचार्यों एवं शोधार्थियों का महाविद्यालय में हार्दिक अभिनन्दन करते हुए सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(प्रो० वीरेन्द्र सिंह)
प्राचार्य

अनुक्रमणिका

Key-Note Address

1. शैक्षिक संस्थाएँः वार्तमानिक परिदृश्य एवं समाहवान **1**

डॉ. पंकज कुमार मिश्र

ABSTRACTS

2. Scheme of Autonomous colleges: Challenge and Opportunities **9**

Dr. Rajpal Bhullar

3. Scenario of Higher Education in Rural India **10**

Dr. Ravinder Kumar

4. Children of leprosy patients: Their psychological and academic performance **10**

Arti Gupta

5. Ethical, qualitative and personality development in current education system **11**

Sudhanshu Singh

6. Gurukula Kangri Vishwavidyalaya: An Institution imparting knowledge as per Vedic/Gurukula system **12**

Dr. Hemwati Nandan

7. Education for sustainable Human Civilization **13**

Sudarshan Naidu

8. Tribal Education in scheduled areas of Madhya Pradesh: Challengesa and Solutions **14**

Dr. Sandeep Kaushik

9. How to improve education system of government school in India? **15**

Dr. Ashish kumar Choudhary

10. Creativity in Classroom Teaching **16**

Dr. Vinod Kumar

11. Principles of Mahatma Gandhi's 'Nai Talim' in NEP 2020 **17**

Aditi Nehra

12. Changing Faces of Education System from Ancient India to Present Digital Education in India **18**

Dr. Sushma Shree

13. How honestly Indian Educationists and Education System Represent the Assertive Voices in School Syllabi? **19**

Bijender Singh

14. Education and Employment among youth **20**

Saurabh

15. Examine the Challenges in the Path of Quality Education in Government Education Institutes **20**

Kiran Fartiyal

16. Educational Aspiration and Scheduled Caste Students Experiences in Schools of Baghpat, Uttar Pradesh **21**

Amit kumar

17. Student Politics in Universities: Should it Banned? **22**

Anurag Kumar

18. India is still laggard in Higher Education: An Analysis **23**
Vivek Kumar

19. Educational Status and Challenges in Ladakh Union Territory **23**
Bashir Ahmad

20. Mentor Teachers: An Innovation in Delhi Education **24**
Vikas Drall

21. Mapping and Analysis of the Educational Status of Haryana **25**
Ashwani

22. Social, Philosophical and Psychological Status of Teachers in Ideologically Inspired Schools **25**
Chetana Shakya

23. New Education Policy: A Path Way to Conducive Development **26**
Vandana

24. Privatisation Of Education: A Boon or A Bane? **27**
Dr. Rahul Chimurkar

25. New Education Policy and Integral Humanism: A Perspective Search **28**
Rohit Bharti

26. Use of ICT tools in Government and Private aided Secondary schools of North Garo Hills, Meghalaya **29**
Prasanna M Sangma

27. Teacher Education after Post-independence period in India: Issues and Remedial Measures **30**
Jan Jahanger, Mudasir Sadiq Dar & Ishfaq Hussain Bhat

28. Role of Buddhist Concepts in the Development of Indian Education **31**
Jyoti Dwivedi

29. Use of Technology in Education **32**
Manisha Jain

30. Challenges and solutions of Primary, secondary and higher education in government sector institutes **33**
Suman Sharma

31. The scenario of Education in Rural areas of Assam **34**
Surajit Gogoi

32. Status of Education in Slum Area **34**
Manu Kajla

33. Secondary Education in India: Issues and Concerns **35**
Dr. Krishna Kumar Pandey

34. Validation of Engineering Self-Efficacy Scale using Mokken Analysis in Indian Context **36**
Jaspreet Kaur, Dr. Rajib Chakraborty

35. Indian Higher Education: Contemporary Challenges and Suggestions **37**
Mrs. Sushma Singh, Dr. Kiran Garg

36. A concept of interrelation between Mathematics and Physical Education **37**
Dr. Anil Kumar

37. Public Expenditure on Elementary Education and Educational Attainment in India **38**
Amritpal Singh Kalsi, Dr. Tushinder Preet Kaur

38. Study of Self-Esteem on the Two Genders of Secondary School: Boys and Girls **39**
Tapasaya Raj Mukker

39. Education For Happiness: A New Approach of Teaching-Learning **40**
Dr. Narendra Kumar, Dr. Rajive Kumar

40. Women Disability: Existing challenges and Future Possibilities to stir up their voices for justice **41**
Ms. Monika, Ms. Sonali Sambyal, Dr. Kiran

41. An Overview of New Education Policy 2020 **42**
Nilofar Anjum Siddiqui

42. Contribution of Dr. B. R. Ambedkar to Indian Education and Society **42**
Dr. Ravikant

43. The Vedic Education System: Present Relevance **43**
Dr Pragyan Dangwal

44. Universal Design of Learning: Critical Analysis with Reference to NEP 2020 **44**
Ms. Preksha

45. Art of Educating Children with Autism and Similar Disorder **45**
Priyanka Tripathi

46. Research on Teaching Leadership, Curriculum development, and effective pedagogy **45**
Sapna Kumari, Dr. Kiran Garg

47. Focus of NEP 2020 on Usage of Technology: Exploring the Scope and Future Pathway **46**
Reecha Jrall, Dr. Kiran

48. Status on Implementation and Challenges of Early Childhood Care and Education in India **47**
Sonalika Biswal

49. Psychological Capacity Building in Teachers **47**
Dr. Soni Kewalramani

50. Prospects and Challenges of Learning Management System in Higher Education **48**
Subhashree Panda

51. The Positive Effects of Technology on Teaching **48**
Mrs. Aapurva Goel, Mr. Puneet Kumar

52. Incorporating Behavioural and Social Science Content in Education **49**
Dr. Jyotsana Shukla

53. प्राचीन भारत में नारी शिक्षा – एक ऐतिहासिक अध्ययन **50**
डॉ. रेखा राजपूत

54. शिक्षा और उसके बदलते आयाम **51**
डॉ. त्रिसुख सिंह

55. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिकतापूर्ण व व्यक्तित्व निर्माण केन्द्रित शिक्षा **55**
ममता शर्मा

56. भारतीय शिक्षा पद्धति का परिदृश्य : भूत से वर्तमान तक **53**
डॉ. निमिश कुमार चौधरी

57. ग्रमीण क्षेत्र में शिक्षा की दशा **54**
परमानन्द महतो

58. कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग **55**
विकास मलिक

59. शिक्षक स्वायत्तता बनाम उत्तरदायित्व **56**
पूरन लाल

60. शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग **57**
डॉ. अनीता सिंह

61. शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव **57**
डॉ0 दिलीप कुमार मौर्य
62. भारत में कृषि शिक्षा और अर्थव्यवस्था में संबंध **58**
डॉ आशीष कुमार
63. वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा एवं विदेशी उच्च शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन **59**
देवराज सिंह
64. शिक्षा का व्यापारीकरण : शिक्षा गुणवत्ता का पतन? **59**
अमित कुमार
65. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण व व्यक्तित्व–निर्माण केन्द्रित शिक्षा **60**
डॉ0 किरन गर्ग
66. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सरकारी शिक्षा में चुनौतियाँ एवं समाधान **61**
सरिता
67. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढंडेरा, विकासखंड नारसन, हरिद्वार (उत्तराखंड) में "प्रगति" पुस्तकालय की स्थापना **62**
अरविंद कुमार
68. "तक्षशिला विश्वविद्यालय" चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण के सन्दर्भ में **63**
अन्जू लता श्रीवास्तव
69. शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी **64**
डॉ0 वीरेन्द्र सिंह
70. शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग **65**
कु. शाईस्ता बेगम
71. शांति शिक्षा का सैद्धांतिक परिदृश्य **66**
प्रवेश कुमार, डॉ0 कविता अग्रवाल
72. नौकरी करने वाली एवं नौकरी नहीं करने वाली विवाहित महिलाओं की जीवन–संतुष्टि के आयामों का अध्ययन **67**
डॉ. पार्वती यादव, अनुराधा उपाध्याय
73. शाहजहाँपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन पर, एक अध्ययन **67**
सुदीप कुमार
74. सरकारी शैक्षिक संस्थान : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां **68**
डॉ0 आजाद प्रताप सिंह
75. योगाभ्यास में निहित औषधीय गुणः पातञ्जल योग के संबंध में अध्ययन **69**
आदित्य कुमार
76. बिहार माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका **70**
ज्योति कूमारी
77. स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था में स्वामी विवेकानन्द की मानव निर्माण शिक्षा की उपादेयता **71**
सुमित कुमार (शोधार्थी)
78. व्यावसायिक वरीयता के लिए व्यावसायिक निर्देशन का महत्व **72**
सुधा
79. नई शिक्षा नीति 2020 **73**
कुसुम सबलानिया
80. शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग **74**
कु . मंजु पाण्डेय
81. अध्यापक और प्रौद्योगिकी **75**
गौरव शर्मा (शोध छात्र)
82. शिक्षा में प्रबन्धन और प्रशासन की भूमिका **75**
हरेन्द्र सिंह

83. नई शिक्षा नीति 2020 **76**
अजय कुमार
84. बिहार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्या और समाधान **77**
अर्चिता कुमारी
85. भौतिक जीवन की सफलता में मूल्य शिक्षा की उपयोगिता **78**
धीरज कुमार वर्मा
86. आधुनिक सन्दर्भ में आचार्य विनोबा भावे के शैक्षणिक विचारों की प्रासंगिकता **78**
अभिषेक कुमार
87. समकालीन शिक्षा तंत्र में मातहत समाज: एक व्यष्टि अध्ययन **79**
शैलेश
88. स्त्री हि ब्रह्मा बभूविय **80**
प्रकृति
89. बिहार माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका **81**
ज्योति कूमारी
90. सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुसार प्राथमिक स्तर में आने वाली बाधाओं का निवारण **82**
मनीषा सिंघल
91. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझावों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता **83**
राजीव कुमार

Key Note Address (आधार व्याख्यान)

शैक्षिक संस्थाएँः वार्तमानिक परिदृश्य एवं समाह्वान

डॉ. पंकज कुमार मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

E-mail: pankaj.k.mishr@gmail.com

सर्वप्रथम यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी शैक्षिक संस्था का तात्पर्य ईंट पत्थर से निर्मित कोई नव्य, भव्य या दिव्य भवन नहीं प्रत्युत वह आकर्षक परिसर है जहाँ जिज्ञासुओं की सर्वविध जिज्ञासा का समाधान यथायोग्य उपाधि के साथ किया जाता है। सामान्य शब्दों में, छात्र अपने समग्र विकास के लिये ज्ञानोपार्जन करता है, जहाँ अध्ययन–अध्यापन का नियमित कार्य नूतन दृष्टि के साथ गतिमान होता हो, वह शैक्षिक संस्था है। इसलिये ऐसी शिक्षण–संस्थाओं का एकमात्र कर्तव्य अथ च दायित्व शिक्षा प्रदान करना मात्र है। क्योंकि शिक्षा वह संजीवनी है जो अज्ञानतारूपी मरुभूमि में भी ज्ञानसरिता प्रवाहित करती है, यह जीवन को प्रकाशमान करती है, चेतना का संचार करती है, व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, राष्ट्र को सत्यं शिवं एवं सुन्दरम् के प्रति मानव को उन्मुख करती है, साथ ही, समाज में व्याप्त अन्धविश्वास और असमानता को दूर करती है। यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्यता है। इसलिये शिक्षाप्रसार ऐसी संस्थाओं का लक्ष्य होता है।

भारतीय परम्परा आदिकाल से ही इसका उद्घोष करती आ रही है– **सा विद्या या शास्ति सा विद्या या विमुक्तये। (विष्णुपुराण)।** एतदर्थ आश्रम, गुरुकुल प्रभृति शिक्षण–संस्थाओं का उल्लेख हमारे शास्त्रों एवं साहित्यों में प्राचुर्येण प्राप्त होता है। शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं की भारतीय परम्परा विश्वप्रथित रही है। यहाँ की शिक्षापद्धति एवं शैक्षणिक संस्थाओं से विश्व का प्रत्येक देश प्रभावित एवं लाभान्वित होता रहा है। ऐसी शिक्षा देनेवाली भारतीय संस्थाओं की बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक शिष्याध्यापक प्रणाली (Monitorial System) से दी जाती थी। वरीय कक्षा के छात्र कनीय छात्रों को पढ़ाते थे और कनीय कनीयतर को। स्वच्छता, शील, शिष्टाचार, कर्तव्याकर्तव्य आदि की शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती थी और प्रत्येक छात्र आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करता था। ये आश्रम इतने विशाल होते थे कि वहाँ एक–एक कुलपति, हजारों उपाध्यायों और ब्रह्मचारियों को पढ़ाने की व्यवस्था करते थे किन्तु कोई भी राजा इन गुरुकुलों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करता था। यह आश्रम गुरुकुल कहलाता था। इन गुरुकुलों का प्रारम्भ वस्तुतः उन परिषदों से हुआ जिनमें पर्याप्त संख्या में विद्वान और मनीषी किसी नैतिक सामाजिक या धार्मिक समस्या पर व्यवस्था देने के लिये एकत्र होते थे। ये गुरुकुल वर्तमान सावास विश्वविद्यालय (Residential University) की तरह होते थे। इन में वेद, वेदांग, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दण्डनीति, सैन्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि सभी विषयों की श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी और जब ब्रह्मचारी, सारी विद्याओं में पूर्ण निष्णात हो जाता था तब उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी आदि विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में परिगणित थे। इसी पारम्परिक संस्थाओं ने आधुनिक विश्वविद्यालयों का स्वरूप ग्रहण किया, जिनके अन्तर्गत नयी व्यवस्था के द्वारा महाविद्यालयों को अंगीभूत किया जाने लगा।

भारतीय शैक्षिक संस्थाएँ एवं उनका वार्तमानिक परिदृश्य

भारतीय शिक्षातन्त्र अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तृतीय सर्वोच्च शिक्षा तन्त्र है। आपाततः भारतीय शिक्षा तन्त्र या संस्थाएँ सर्वथा आकर्षक ज्ञानोपयोगी एवं अपेक्षानुकूल प्रतीत होती हैं किन्तु वैश्विक

मानदण्ड पर यथापेक्ष नहीं है। गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। पुनरपि, सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, शिक्षार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। शिक्षा–व्यवस्थापनार्थ विनियोग में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है। ऐसा होने पर भी उच्च शिक्षा की सुलभता, गुणवत्ता एवं परिष्कार यथार्थगत नहीं है। बल्कि आकर्षक भवन निर्माण तो होते चले जा रहे किन्तु आज भी उस लक्ष्य की प्रतीक्षा लम्बी ही होती जा रही जिस लक्ष्य की इच्छा से उन भवनों एवं परिसरों का निर्माण किया गया या किया जा रहा है। यह एक ऐसी समस्या अथ च समाह्वान (चुनौती) है जो सुरसा के मुख की तरह फैलता ही जा रहा है। इन समस्याओं को उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में कतिपय अग्रांकित सूचनाओं से समझा जा सकता है–

- भारत में उच्च शिक्षा के लिए पंजीयन कराने वाले छात्रों का अनुपात विश्व में न्यूनतम अर्थात् केवल 11% है। अमरीका में ये अनुपात 83% है।
- नैसकॉम और मैकिन्से के शोध के अनुसार मानविकी में 1/10 और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके 1/4 भारतीय छात्र ही नौकरी के योग्य हैं। भारत के पास विश्व की सबसे बड़े तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति है– यह कथन एक विरोधाभास मात्र प्रतीत होता है।
- NAAC के अनुसार भारत के 90% कॉलेज और 70% विश्वविद्यालय स्तरहीन हैं।
- भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की न्यूनता तो कल्पनातीत है ही, IIT सदृश संस्थानों में भी 15 से 25% शिक्षकों की कमी है।
- भारतीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री के निर्माण में भी विफल ही हैं। योजना आयोग के सदस्य और पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति नरेंद्र जाधव के अनुसार कई विश्वविद्यालयों में पिछले 30 सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- अच्छे शिक्षण संस्थानों की न्यूनता के कारण अच्छे संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता। फरवरी 2017 तक देश में 789 विश्वविद्यालय और 37204 कॉलेज थे।
- अध्ययन से ज्ञात होता है कि अच्छे अंक लाने की स्पर्धा के कारण छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है।
- धन की कमी भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के रास्ते में एक बड़ी बाधा है।
- भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 43 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च करते हैं क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन स्तरहीन है।

आश्चर्य है कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में शोधोपाधियाँ प्रदान तो की जाती है किन्तु यदा कदा ही किसी एक दो शोध को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल पाती है। दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमेरिका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत से केवल 3% शोधपत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं।

किसी शिक्षाशास्त्री का यह कहना था कि आने वाले दिनों में ज्ञान का समाज विश्व के किसी भी समाज से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जाएगा। विश्व में गरीब देश कदाचित् विनष्ट हो जाएं पुनरपि किसी देश की समृद्धि आकलन इस बात से किया जाएगा कि वहाँ की शिक्षा का स्तर कैसा है।

संस्थागत समस्या

भारत के राज्यों में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारियों की संख्या शिक्षा विभाग में ही देखने को मिलती है। इसमें भी अध्यापकों के अतिरिक्त अधिकारी और प्रशासक भी हैं जो हमारे शैक्षिक सेट–अप का एक

महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान उन्हीं शैक्षिक परिधि में रखा जाता है। यहाँ भी यदा–कदा समन्वयात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है जो शैक्षिक कार्यजात को आहत करता है। इसके अतिरिक्त–

उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा अंश राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों से आता है, जबकि इन राज्य विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। UGC के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही मिलता है।

वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों के दायित्व और प्रदर्शन सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों के विपरीत है, जहाँ फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा का सशक्तीकरण

शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इससे छात्र उच्च शिक्षा के लिये साथ ही जीविकाविषयक कार्य के लिये तैयार होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन तथा जीवन–स्तर को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने की आवश्यकता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्षों की अवधि में स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल में परिष्कार हो।

इसके लिये केंद्र प्रायोजित योजना में विभिन्न शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ताकि लोगों की जीविका क्षमता को बढ़ाया जा सके और कुशल जनशक्ति (Skilled Workforce) की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिये एक विकल्प उपलब्ध कराती है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सशक्तीकरण से 2022 तक 50 करोड़ कुशल कर्मियों के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

गुणवत्ता की समस्या

शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। देश के शिक्षासंबंधी सभी अध्ययन और सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का स्तर भी अपेक्षा से नीचे है। विद्यालयों/महाविद्यालयों की मूलभूत संरचना और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अत्यन्त स्तरहीन है। देश में लाखों विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक है। ऐसी स्थिति में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक होगा। शिक्षक भी अपने आप को नवीनतम जानकारियों से लैस नहीं करते इससे जो छात्र डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, उनकी जानकारी का कोई उपयोग विकास के क्षेत्र में नहीं हो पाता।

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार की आवश्यकता है। अभी शिक्षण की विधियाँ राज्य स्तर से तय की जाती हैं, जिनमें कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है।

उच्चतर शिक्षा पर शोध करने वाले पूर्व आईएएस अफ़सर पवन अग्रवाल कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इस धारणा को बदला जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को भद्र बनाना है।

21वीं शताब्दी की शिक्षा को तब तक स्तरीय नहीं बनाया जा सकता जब तक स्कूली शिक्षा 19 वीं सदी में विचरण कर रही हो। यह एक कटु सत्य है कि भारत के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में

कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं होती। यद्यपि स्कूली शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हुई है तथापि गुणवत्ता की समस्या बनी हुई है।

शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी और जरूरी संसाधनों का अभाव एक भीषण समाह्वान है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल पदों की संख्या 16,602 है। इनमें से 6542 पद रिक्त हैं। एक सूचना के अनुसार **प्रत्येक विश्वविद्यालय में लगभग 45% से लेकर 52% तक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें 44.6% पद प्रोफेसरों के हैं।** UGC के अनुसार, कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर, 46% एसोसिएट प्रोफेसर और 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। लगभग हर राज्य के विश्वविद्यालयों की यही स्थिति है।

केन्द्र सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिये निरन्तर प्रयास करती रहती हैं। लेकिन इसमें राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के असफल हो जाने का संकट रहता है, क्योंकि वे परिवर्तन करते समय रोडमैप का अनुसरण नहीं करते और नीतियाँ बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता।

छात्रों की प्रवर्धमान संख्या के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना परिस्थिति की माँग है। भारत में महाविद्यालयों की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के विकास में बाधा मानी जाती है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को सम्बद्ध महाविद्यालयों की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान किया जाय। किन्तु आश्चर्य यह है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना के विपरीत महाविद्यालयों की ही स्थापना महत्त्वपूर्ण है। महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों पर बढ़ती निर्भरता एक अतिरिक्त बोझ सिद्ध होने लगी है।

एतदर्थ कतिपय गंभीर किन्तु कटु निर्णय की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए–

- शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना,
- शिक्षा के व्यवसायीकरण पर नियन्त्रण,
- आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या वृद्धि
- प्राविधिक संस्थाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना

भारत का उच्च शिक्षा तन्त्र : चुनौतियाँ तथा समाधान

भारत में उच्च शिक्षा का नियन्त्रण तथा गुणवत्ता निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग का दायित्त्व विश्वविद्यालय प्रणाली में समन्वय, निर्धारण और अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के लिए उचित मानदण्ड आदि का निर्धारण कर उन्हें नियमित रखना है।

केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा भ्रामक विश्वविद्यालयों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यूजीसी अधिनियम में बदलाव कर इसके स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना करने का फैसला लिया गया। ऐसे समय में जब कौशल निर्माण तथा शैक्षिक अवसरों तक पहुँच होना अति महत्त्वपूर्ण है, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किये गए उच्च शिक्षा आयोग के प्रावधानों के प्रभाव दूरगामी सिद्ध हो सकते हैं।

2022 तक उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूजीसी ने एक योजना प्रस्तुत की है–

- न्यूनान्यून 50% स्नातकों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाए।

- सार्थक गतिविधियों के द्वारा समाज और उद्योग जगत से छात्रों का सम्बन्ध सुनिश्चत किया जा सके।
- छात्रों में टीम भावना, संचार और नेतृत्व के गुणों, उद्यमिता के भाव तथा निर्णय लेने की क्षमता के समावेश के प्रयास किए जाएंगे।
- किसी भी समय शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत से अधिक रिक्त न रहें।
- उच्च शिक्षा के प्रत्येक संस्थान को राष्ट्रीय आकलन एवं प्रमाणन परिषद (नैक) से वर्ष 2022 तक कम से कम 5 अंक के साथ मान्यता प्राप्त करनी होगी।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूजीसी ने कई पक्षों के साथ एक योजना भी बनाई है, यथा–

- परिणाम आधारित शैक्षिक संरचना (ओबीई) को स्वीकार करने का निर्णय
- नियमित अन्तराल पर पाठ्यक्रमों को पुनरावृत्ति।
- अध्यापन के लिए सूचना, संचार एवं तकनीक आधारित माध्यमों की सहायता।
- शिक्षकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण। शिक्षा प्रशासकों के लिए नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन का प्रशिक्षण।
- कोई भी स्वायत्त–संस्थान NAAC से वर्ष 2022 तक मान्यता प्राप्त कर सकता है।

भारतीय उच्चशिक्षा में अनिवार्य परिवर्तन

भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था काफी पुरानी हो चुकी है। आज की स्थितियों से उसका कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। अब उसमें ऐसे बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि इस शिक्षा का सही उपयोग हम अपने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कर सकें।

भारतीय जनसंख्या में युवाओं की संख्या 51% है, लेकिन इनमें से मात्र 12–14 प्रतिशत लोग ही (18–24 साल तक के छात्र) उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। चीन की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। दूसरे विकसित देशों से तो कोई तुलना ही नहीं है। जैसे अमेरिका में 82 प्रतिशत और रूस में 75 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा के लिए अपना नामांकन कराते हैं।

नीचे गिरता स्तर आज एक लाख से ज्यादा भारतीय छात्र अकेले अमेरिका में पढ़ रहे हैं। इस तरह अमेरिका जैसे देश अपनी उच्च शिक्षा की बदौलत विदेशी छात्रों से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं और उसे अपने विकास में लगा रहे हैं। इसके उलट, हम अपने ही छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाने के कारण अपनी मुद्रा गंवा रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं।

एसोचैम ने 2008 में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत यहां से पढ़ने के लिए विदेश जाने वाले छात्रों से कुछ राजस्व लिया जा सके। इस राजस्व को देश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगा कर हम अपने संस्थानों को विश्वस्तरीय बना सकते हैं। इससे यहां शिक्षा के विकास के साथ–साथ रोजगार का भी सृजन होगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पढ़ाई के लिए आए विदेशी छात्रों की कुल संख्या 30 हजार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 4 लाख और सिंगापुर में डेढ़ लाख विदेशी छात्र पढ़ते हैं। विदेशी छात्रों को अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए या छात्रों को स्तरीय शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि हम अपने संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर सुधारें।

हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में छात्र अपनी रचनात्मकता को मारता है और भाग्य को साथी मानकर परिस्थितियों को सहन करना सीखता है। इससे ऊर्जा व समय–दोनों का अपव्यय होता है। हमारा वर्तमान उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम एक जैसा कार्य करने के लिए तो ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत समय से कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन ऐसी पढ़ाई को लगातार अपग्रेड करने, उसे अनुसंधानपरक बनाने और उसे प्रैक्टिल ट्रेनिंग पर आधारित बनाने की आवश्यकता है।

सरकारी संस्थानों के अधिकांश प्राध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता की उपेक्षा कर वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न दीखते हैं। एक अवसर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारे शिक्षक छात्रों को पढ़ने के लिए आकर्षित करने में विफल रहे हैं। क्या वे सचमुच विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं? वे खिड़की से बाहर झांक कर देखें कि निजी संस्थानों में पढ़ाने वाले उनके समानधर्मी शिक्षक नौकरी की सुरक्षा और वेतन कट जाने के भय से किस तरह प्रबंधन की धुनों पर नाच रहे हैं, क्योंकि वहाँ काम और आउटपुट की उपयोगिता है।

इसके अतिरिक्त हमारा शिक्षा तंत्र अन्य कई विभागों की ही तरह भ्रष्टाचार से भी ग्रस्त है। परिवर्तित मूल्यांकन प्रक्रिया के होने पर भी योग्य की नियुक्तियां नहीं हो पाती है। स्तरहीन पुस्तकों को पाठ्यक्रमों में लगाने की अनुशंसा की जाती है। मौलिक शोध बहुत कम होता है। सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संबंधित संकाय द्वारा विकास कार्यक्रमों का अनुपात काफी कम है। मानवीय कोणों से अध्ययन करने में भी तीव्रपतन आ रहा है। शिक्षकों की कार्यपद्धति पर कोई नियम आरोपित नहीं किए जाते, न ही उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। सारे विश्वविद्यालय राजनीति की आधारभूमि बन गए हैं। वहाँ के चुनाव पार्टी लाइन पर लड़े जा रहे हैं। कुलपतियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। शैक्षिक सत्रों में हड़तालें की जाती हैं, कक्षाओं का बहिष्कार किया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन प्रक्रिया में आमूल–चूल सुधार की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि एक प्रबुद्ध शिक्षक और कुशल छात्र ही मानव शक्ति का विकास करता है, अन्यथा वह भारस्वरूप है।

किसी भी देश की शिक्षा–व्यवस्था कितनी उन्नत है, इस तथ्य का मूल्यांकन तीन मानदण्डों पर किया जाता है। प्रथम– उच्च शिक्षा तक कितने युवाओं की पहुँच है; द्वितीय– क्या उच्च शिक्षा न्याय–संगत है? और तृतीय– उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है? यह बहुत दुःख की बात है कि इन तीनों ही मापदंडों पर हम विफ़ल रहे हैं।

अस्तु, यह कहना किंचित् ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भारत में उच्च शिक्षा रुग्ण अवस्था में है और पुरातन तथा जीर्ण–शीर्ण हो चुके आधारों पर टिकी हुई है। वस्तुतः शिक्षा के बिना मानव जीवन व्यर्थ समझा जाता है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उल्लेखनीय प्रयास भी किये गए हैं. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया है, किन्तु उच्च शिक्षा की राह में अब भी अनेक बाधाएँ हैं और गुणवत्तापरक शिक्षा अभी भी दिवास्वप्न बनी हुई है।

कवीन्द्र रवीन्द्र ने स्वतन्त्रता के स्वर्ग में, जागरण के आलोक में, रुचि और अन्धविश्वासों के विरुद्ध, मौलिक चिन्तन और अबाध प्रगति के प्रेरक विवेक में अपने राष्ट्र के जगने की प्रार्थना की थी। यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम योग्य शिक्षा, सुयोग्य शिक्षार्थी एवं सत्य शिव एवं सुन्दर के लिये समर्पित शिक्षा संस्थानों का वायुमंडल तैयार करें। राष्ट्र के कण कण से जन जन के लिए मन मन से शिक्षासंस्थानों के समुत्कर्ष की अभिकामना निकले।

ABSTRACT

Scheme of Autonomous colleges: Challenges and Opportunities

Dr. Rajpal Bhullar
Head Deptt. of Poltical Science, D.A.V. College Naneola (Ambala)
E-mail: Rajpalbhullar@gmail.com

The affiliating system of collegesa was originally designed when their number in a university was small. The university could then effectively oversee the working of the colleges, act as examining body and award degree on their behalf. The system has now become unwieldy and it is becoming increasingly difficult for a university to the varied need of individual colleges. The collegesa do not have freedom to modernize their curricula or make them locally relevant. The regulations of the university and its common system, governing all the collegesa alike, irrespective of their characteristic strength, weakness and locations, have affected the academic development of individual colleges. Due to affiliated system collegesa that have the potential for offering programmesa of a higher standard do not have the freedom to offer them. The 1964-66, Education Commission pointed out that the exercise of academic freedom by teachers is a crucial requirement for development of the intellectual climate of our country. Unless such a climate prevails, it is difficult to achieve excellence in our higher education system. With student, teachers and management being co-partners in raising the quality of higher education, it is imperative that they share a major responsibility. Hence Education Commission (1964-66) recommended college autonomy, which, in essence, is the instrument of promoting academic excellence.

The National Policy on Education (1986-92) emphasized this educational reform as a planned intervention through UGC, university and state governments. Under the scheme the collegesa has to establish its own set of admission rules, curriculum, examination and evaluation schedule with appropriate strategiesa for independent functioning. There is a creative freedom which permits area specific studiesa and combination of coursesa without any dependence on university prescribed procedure and syllabi. An autonomous college has to strive towards overall planned development while maintaining its functional independence. It has to be its own policy formulator and has to match its declared objective with actual performance. The financial support of 9 lakhs for single faculty and 15 lakh for more than one faculty U.G. autonomous college and 10 lakhs for P.G. single faculty and 20 lakh for more than one faculty P.G. college will be provided by the UGC, as per UGC latest guidelinesa and scheme for autonomous collegesa maintenance of standard regulations 2018. Till now, out of 39931 total collegesa in India only 708 Collegesa are approved as autonomous collegesa by university grant commission. There are about maximum 193 collegesa in the Tamil Nadu that have an autonomous status. Andhra is in second state of India where 104 collegesa are enjoying autonomous status. It is matter of observation and research that why the most of collegesa situated in northern Indian state are not taking interest in the UGC scheme of autonomous status.

Scenario of Higher Education in Rural India

Dr. Ravinder Kumar
Assistant Professor, Department of Chemistry, Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar
E-mail : ravinder.kumar@gkv.ac.in, drravinderdu@gmail.com

It was once rightly said by the father of our nation Mahatma Gandhi that ***'India livesa in its villages'***. People residing in villagesa represent the true image of **'Real India'**. However, due to lack of literacy and education, the rural India witnessesa many drawbacks.

Majority of India still livesa in villagesa and so the higher education in rural India is of utmost importance. A survey named called the Annual Status of Education Report (ASER), shows that even though the number of rural students attending schools is rising, but more than half of the students in fifth grade are unable to read a second grade text book and are not able to solve simple mathematical problems. Not only this, the level of mathematics and reading is further declining. Though efforts are being made, they are not in the right direction. So you can imagine the status of higher education. it is not about just shortage of money or just shortage of trained teachers or lack of political will.

Children of leprosy patients: their psychological and academic performance

Arti Gupta
Department of Clinical Psychology, Dev Sanskriti Vishwavidhyala, Haridwar, Uttrakhand
Email: dr.aartigupta82@gmail.com

The purpose of present study was to investigate the adjustment and academic performance of healthy children of leprosy affected parents. The respondents for this purpose were the children of leprosy patients studying in institutions specially made for them by Government and NGO. 200 children (100 Boys and 100 Girls) of standard VIIIth and IXth were selected as sample. Adolescence adjustment scale developed by Mrs. Ragini Dubey was used to measure students' adjustment and last one year academic performance of the student was taken which included both his class room learning and his participation in extracurricular activities. The obtained data were analyzed in terms of mean SD, Co-relational analysis and t-Test. Results revealed that adjustment scores of the respondents were highly significant correlated with their academic performance scores. It was also found that boys and girls were quite alike in case of their adjustment and academic performance but in respect of extracurricular activities boys' participation was found higher than the girls.

Keywords: Leprosy; Adjustment; Academic performance; Extracurricular Activities

Ethical, qualitative and personality development in current education system

Sudhanshu Singh

Principal Consultant, Feedback Infra, Gurugram

The focus of education in India is on its economic benefits. It is a means to an end – a good job, creating a workforce for the economy. When academics study education, again there is more focus on the employability of graduates, economic returns to students, optimizing spending in education etc. Although there have been various criticisms about the curricula provided in schools, we have not yet questioned the basic system of education which we took over at the time of India's independence. We have not done that because we have never thought of education except in terms of producing engineers, doctors, lawyers and clerks to work for the modern industrial economy.

There are other reasons and benefits of education to the individual and the society that are equally, if not more important, such as: Self-Realization; Cultivation of Moral Values; Conservation, Promotion and Transmission of Culture; Co-Operative Living; and Development of Physical Health.

India facesa many social issues. The impact of some of these can perhaps be reduced by including in education components which teach our young generation on how to manage and address them. Education is one of the most important pathway to success for disadvantaged groups. Properly instituted physical education programs can promote public health over the life span. With increasing technological changes, there is a need to address the gap between the capabilitiesa of our population to handle this technology as well as benefit from it.

In this article, we try to highlight on what should the objectivesa of education in India other than its direct economic benefits.

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya: An Institution imparting knowledge as per Vedic/Gurukula system

Dr. Hemwati Nandan

Department of Physics, Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar (U.K), India

E-mail: hntheory@yahoo.co.in

Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar is run by Arya samaj was founded in 1902 by great arya samaj monk Swami Shardanand ji with the sole purpose to revive the Indian Gurukula system of education. This institution was established with the objective of providing an indigenous alternative to **Lord Macaulay's** education policy by imparting education in the areas of vedic literature, Indian philosophy, Indian culture, modern sciencesa and research. It is a deemed to be university fully funded by UGC/Govt. of India.

Arya Samaj has been advocating women's education since the day it was founded. As part of its policiesa for the up-liftment of women in the country, Kanya Gurukula Campus, Dehradun was established in 1922 by **Acharya Ramdevji** as a second campus of women's education. To give real shape to the dreams of Swami Shraddhanandaji, Kanya Gurukula Campus, Hardwar was established in 1993.

At present various coursesa related to Vedic literature, Vedic science and Indian philosophy are hereby taught at different department. In this paper, we present a detailed information of GKV Haridwar with its role especially in context to the present system of the Indian education system.

Education for sustainable Human Civilization

Sudarshan Naidu

Sr. Consultant, Indian Council of Social Welfare, Delhi

E-mail: sudarssan@gmail.com

This paper attempts to reveal the varied facts and factors that have made what was once a celebrated Indian education to mere rote –memory routine and what was once the jagat guru to present days of clerical services; Exceptional personalitiesa are also cited of timesa but the majority trend is also narrated starting from Waywardness in the name of liberal education to several of controversial imagesa created of Indian Education Systems. The significant issue being highlighted are the repairing and updating required but vested interests have taken it for a generalization in the name of liberalization. The important aspects are: Charity vs commercialization, Integration and differentiation, Error vs faults, focusing vs Open ended answers, Rote memory vs inquisitiveness, Listening vs learning, Practical approach, Problems of primary education, Wastage of resources, Mass illiteracy, Brain drain, Indian languagesa neglected, Expensive higher education, Fund crunch.

Gurukul systems requiresa periodical updations, it required suitable amendments, supportive contributions, broad basing, ABCD, XYZ, but vested interests have replaced it with a totally an alien format and formula, by exploiting the situation, instead of reviewing and updating itself.

This paper is a call for policy makers and advocatesa of learning systems and learning way of generations to become aware of the greatness of Gurukul systems and urgesa to have few centresa as an optional form of learning that should be made available to citizens.

Tribal Education in scheduled areas of Madhya Pradesh: Challengesa and Solutions

Dr. Sandeep Kaushik
Department of Environmental Science, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, (Madhya Pradesh)
E-mail: sskaushik2002@gmail.com

Praveen Shyam
Department of Environmental Science, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, (Madhya Pradesh)

India has the second largest tribal population in the world forming an integral part of the Indian society and constitutesa nearly nine percent of the total population of the country (as per census 2011). The Amarkantak region, a part of Anuppur district is a unique natural heritage area and is the meeting point of the Vindhya and the Satpura Ranges, with the Maikal Hills being the fulcrum. The strategic geographical location with rich variety of flora and fauna, leading to enchanting flush green forest, is inhabited mostly by the indigenous or tribal population. The present paper deals with a case study which was carried out under the Unat Bharat Abhiyan 2.0 (UBA 2.0) to ascertain the challengesa associated with tribal education/literacy inselected areas of district Anuppur and strategically pointing to the possible solutions. The Tribal population is mainly confined to geographically or naturally isolated areas such as forest hills making them even more deprived of the government policies. Education can thus be a foremost factor for transformation of these areas not only in terms of economic basis but also their social stature, inclusive and sustainable growth - the basis of their customary well being. Currently, the area lags behind in terms of male-female gap in literacy, proper educational attainment even at the elementary and secondary education level the basis for their linkup with the outside world. The primary challengesa pertains to geographical location of the village/school, lack of infrastructure and teachers/mentors, high transfer rate of the school teachers, medium of instruction, poor economic condition, and very low literacy rate among the parents, lack of proper monitoring by the district authorities, lack of awareness wrt education among the tribal population etc. The possible solutions are appointment of mentors/teachers at gram panchayat level, inculcation of NGOs and making mandatory/compulsory teaching of the students pursuing internship at diploma and degree in education in tribal areas, introduction of volunteers of the undergraduate and postgraduate students to carry out teaching in selected schools, introduction of government policiesa boosting their morale and economic abilitiesa such as scholarships-residential schools, medium of instruction to be in their local language especially at elementary level and proper monitoring by the local, district and state authorities.

How to improve education system of government school in India?

Dr. Ashish kumar Choudhary

Departmnt of Botany,Deshbandhu College, University of Delhi, Delhi

Email: ash4biotech@gmail.com

Government schools are an essential part of our society and serve the majority of children in our country. These schools are affordable to every section (poor to rich) of our society. As per Right to education (article 21a) of the Indian Constitution, it provide education to every child between age 6 to 14 and government schools play a major role to provide education to every child. In government schools, the education is deteriorating. Education is deteriorating in the government schools across India because of absence of teachers, lack of professionally qualified teachers, Poor allocation of funds, insufficient classrooms, shortage of furniture, absence of innovative teaching, absence of advance learning equipment, absence of advance training program for teachers, not fully developed science laboratoriesa and library, absence of international standard of education, no international collaborations, broken roofs, dirty toilets and unhygienic mid-day meals. Many Government schools exist on paper only because their infrastructure is fully or partially ruined. In rural areas, most of the government schools are not proper schools but confined to one room. These are main issuesa to low attendance and high drop-out ratesa from the Government schools. In the last two years, government schools have lost six million children. Parents are rushing to private schools of good repute for admission of their children. But, private schools are not affordable for every parent because of their high fee structures. The government needs to improve basic infrastructure and teaching quality of the government schools to provide better education to children. We could improve our education system of government schools in the following ways:

- Develop basic infrastructuresa like classrooms, laboratories, the library, and playgrounds.
- Recruitment of professionally trained teachers
- Innovative teaching process
- Promote cultural and sport activities
- Regular monitoring of school progress by higher authority
- Promote extra-curriculum activitiesa like debates, promote regional and international languages, nukkad natak, seminars, science outreach program etc.
- Collaborations at national and international levels

Creativity in Classroom Teaching

Dr. Vinod Kumar

Asistant Professor, Special Centre of Nano Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi

E-mail: vinod7674@gmail.com

A good classroom environment always has some elements of creativity which makes the lessons more interesting and interactive. Creativity is the major possessions in the education and classroom teaching. Students can grow up as good communicators in addition to improving their social skills. Creativity is based on the innovation used while teaching young minds. A creative teaching needs some of the crucial points and are follows:

1. Clarity while presenting the topic
2. Proper analysis and difficultiesa in the topic
3. Usage of common and day to day examplesa to explain the topic
4. To understand the psychologically of the students
5. Involvement of the students in the teaching such as group discussion, thoughtful question-answer, etc.
6. Utilizing Information and Communication Technology (ICT) along with chalk and duster
7. Pedagogical tools must be used during the class
8. Several perspectivesa and challengesa along with appropriate solution related to the topic

Creative teaching is far better than good teaching through which develop and inculcate true valuesa among the young minds. The pleasure of creativity also contributesa a lot to improved health and this helps them to have a continued growth in academics as well as world of relativity. During a TED talk, Sir Ken Robinson raised the utmost significance of creativity in today's education when he told "Creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status." Every child has some inbuilt creativity in them and proper guidance from the teacher coaxesa and cultivatesa it to help them grow up as creative individuals.

Principles of Mahatma Gandhi's 'Nai Talim' in NEP 2020

Aditi Nehra
BA, MA, B.Ed.

"An education which does not teach us to discriminate between good and bad, to assimilate the one and eschew the other, is a misnomer." M.K. Gandhi

Recently The 150th birth anniversary of M.K. Gandhi, has been celebrated around the globe. He was a multifaceted personality having in depth and thorough ideas on different aspects of both human life and social life right from philosophy, economy, polity, education, science and technology, psychology, values and morality, trade and commerce to international peace and harmony.

Gandhi's realization that the British system of education could not serve the socioeconomic need of the country. In 1937, Mahatma Gandhi seeded an important idea to revamp the education system, 'The Wardha Scheme of Education' or 'Nai talim' for modern India, which can be called the first blue print of national system of education, which is job centered, value-based and mass oriented. It is the first model of vocationalisation of education in India. This scheme was the first attempt to develop an indigenous scheme of education in British India.

According to him, knowledge must be related to activity and practical experience. His scheme of education envisages, a close integration between the school and the community so as to make child more social and co-operative.

"The function of 'NAI TALIM' is not merely to teach an occupation but through it develop the whole men." M.K Gandhi

However, Nai Talim always remained a peripheral system and could never integrate with the mainstream education till recently. The reasons for the lack of mainstreaming of Nai Talim approach happened due to the ways in which this approach was perceived by consumers of education. With the changing structure and form of the society, there were changes in the expectations of outcomes of education.

However, the NEP 2020 brings in a new hope that Gandhi's vision would be fulfilled if the policy is implemented with the same intent with which it was drafted. Some Nai Talim's approach offered by the NEP are:

1. Nai Talim approach emphasized on the importance of education through any productive work that we do in our everyday life (learning by doing).
2. Nai Talim approach focused on imparting education in mother tongue based on the logic that familiarity in language being used in home as well as school would help the child to see the school as a natural extension of home.
3. Nai Talim focused on nurturing multiple skills in a child based on her/his interest.
4. Nai Talim approach presented a concept of learning that went beyond textbooks.

According to Gandhi, quality education focuses on the learner's complete growth and instil values like non-violence, honesty, and resilience to build a sustainable society. We believe that the vision of holistic education envisioned by Gandhi, and recommended by NEP, would help create a brighter future for our nation.

Changing Faces of Education System from Ancient India to Present Digital Education in India

Dr. Sushma Shree

Post Doctrol Fellow, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Bihar

E-mail: kumarisushmashree598@gmail.com

This paper is going to throw light on the aspect how digital Education System has changesa the way of teaching and learning from ancient education system to the present Digital way of education. In Ancient India there was different education system: -

a) **Gurukul education system**: where pupils livesa with their guru and help them in their daily chorus and Guru taught them about Spiritual, Religious and Vedas.
b) **Education in Medieval India**: After the Islamic invasion of India education system has changed. The rising influence of Islam led to establish of Madrassa for Muslims and Vedic schools for Hindus.
c) **Education in colonial period:** British stress on English (missionary) schools. The main aim of the missionariesa was to convert the native Indian to Christianity.
d) **Present Education system:** Soon after independence in 1947, giving education to all was a priority for the government. The present education system in India mainly comprisesa of primary, secondary, senior secondary and higher education. The changing method of teaching and learning form Black board to smart board to smart class and E-learning has taken a boon in educations system. Paper will highlight on all aspect mention in para.

Keywords: Gurukul system, medieval system, colonial system, Education in 2000 era, Modern methods of teaching like smart board, smart class, E learning.

How honestly Indian Educationists and Education System Represent the Assertive Voices in School Syllabi?

Bijender Singh

Assistant Professor, Dept. of English, Indira Gandhi University, Meerpur (Rewari) Haryana

Email: bijendersingh8t@yahoo.com

This paper aims to explore the honesty and truthfulness of included assertive voicesa in school syllabi in India. Some decadesa ago, the school syllabi were completely devoid of the radical voicesa that contributed enormously to Indian society to promote the equality and human rights of marginalized people. Since no society can remain unaffected of the vociferous voicesa for a long time. Consequently, these voicesa not only were revisited by the government and educationists but were included in the school syllabi to make students acquainted with these iconoclasts and their ideas. In this attempt, what these revolutionariesa did for society became part of syllabi but the evils they fought against were totally neglected. As Krishan Kumar arguesa that schools and syllabi in fact propagate the dominant structuresa and continue social hierarchies, the school syllabi did not mention the social evil/structure these revolutionariesa fought against. Based on some of the school syllabi and some autobiographical narratives, this study attempts to prove that either there is no representation or only misrepresentation of marginalized revolutionaries. This has been practised intentionally to cover the social evils, mainstream people were prejudiced of, which were inhuman and exploitative in nature; to undermine the ideas and actions of the marginalized revolutionaries; and conceal those inhuman theory and praxis the mainstream people of India were proud of. All these attempts of misrepresentation prove intellectual/academic dishonesty of Indian educationists and government.

Key Words: Assertion, Misrepresentation, School, Syllabi, Honest, Voices

Education and Employment among youth

Saurabh

Senior program Manager, Piramal Foundation.

E-mail: saurabh.jnv.dj.iitr@gmail.com

Youth population is one of the greatest asset for India. There are more than 450 million youth in the country. India can keep its growth momentum if she can make this group of population employable. However, in current scenario India is struggling in tapping immense potential of this group of the population. According to ILO report published in 2012, only 4% of Indian population could be employed in organized sector. India is among those countriesa where youth unemployment is highest. More stark reality is that the unemployment rate increasesa with educational qualification. More that 60% of the youth are employed in entry level jobs and 90% of the youth are employed in informal sectors.

Primary cause of this painful scenario is the lack of employability skills curriculum in our education system and absence of a formal career guidance platform. In addition, parents who play key role in youth employment are unaware about changing employment opportunities. In Hindi belt youth still focusesa on government jobs as employment opportunities. The populous statesa like Uttar Pradesh, Bihar and Bengal lacks entrepreneurial attitude and the youth suffer the most because of this.

To tackle the above problems, and to tap the youth potential, India needs seismic changesa in education and skill training infrastructure. Education in India must be inclined towards entrepreneurship and employability skills. The youth must need to be trained in behavioural skills and must be incubated to develop entrepreneurial attitude. There must be a parallel curriculum in every education system. These measuresa may take time but whenever implemented will lead Indian youth towards bright future and Indian economy will keep growing for foreseen period.

Examine the Challenges in the Path of Quality Education in Government Education Institutes

Kiran Fartiyal

Research Scholar, Department of sociology, MBGPG College, Haldwani, Uttrakhand

This paper aim to examine the challenges in the way of Government Education institutes to provide the quality education to their students. Generally the government focused on accelerating the enrolment of the students and give less priority to the standard education, for which private education institution charge a huge amount of money which is near impossible to the poor students to get enrolment there for better education. Due to lack of quality education in Government Education Institutes, even after getting degree they suppose to be like the illiterate educate students and suffer from the other problems like unemployment. Thus education is one of the main root causes of other's dilemma. Therefore, if the focus of the government will move on the quality education then naturally the enrolment of the students will elevate in Government education institution. This paper is descriptive and analytical in design, based on secondary sources of data. The study is carried out with the help review of literature available on these institutions. This study is significant to look at the factors which hamper the Government Institution to become more advance and better, so they play an important role in the development and growth of the country.

Educational Aspiration and Scheduled Caste Students Experiences in Schools of Baghpat, Uttar Pradesh

Amit kumar
PhD scholar, Indian Institute of Dalit Studies (IIDS), New Delhi.
Email:- amitgautam15@gmail.com

Education is a necessity, a right which plays the most valuable take for creating a bright future of a child. It is assumed and proved by many thinkers and authors that the higher level of education is associated with higher income, a more prestigious career, lower risk of unemployment and an improved well being. It is also a key factor in promoting and sustaining economic growth and social development. There are many determinants of lagging for a marginalized group such as discrimination, lack of infrastructure, employment, lack of local inspirational environment, lack of parental support, scarcity of guidance/counseling and so on. The aspirations for education and occupation not being developed in these students due to poverty and low educational background of the family which results in low performance, unhealthy/ignorance environment of education and lastly they drop out or forced to engage in traditional occupations. The largest group of children who have dropped out of school are mostly first-generation learners (Draze & Sen, 2003). This has indicated the unawareness of education policiesa and structure which further indicatesa one of the reasons for unemployment in disadvantaged groups. There has been a study which shows that the children from Scheduled Caste are very few who reach University-level education and within that, the ratio of girls is still very low (Ramaiah, 1998)**.** So they suffer mostly within the sphere of employment and dignified life. These children live in an environment that is not conducive to study and in a situation where knowledge about how to access and negotiate schooling is limited (Bandyopadhyay, 2008; Reddy, 2004). At primary and secondary levels at school, the child starts understanding the moral lesson of society which leads to future achievement and aspirations.

Besidesa various Commissions and National Policies, the Five Year Plans have been envisaging programs under various sectors of development for the benefit of disadvantaged sections, including children from Scheduled Caste. These calls for making educational provisions at the secondary and higher secondary level also as the universalization of elementary education are likely to create a demand for education at the next (secondary and higher secondary) level (Kumar, 2012).

Access to education by caste can be, and has been analyzed at various levels literacy rates, quality of education primary to middle school transition and evidence of discrimination inside schools from the strict point of view of implementation of affirmative action, however we need to focus on a few key rolesa such as the counseling, approach to achieve aspiration. When a student studiesa in the secondary or senior secondary level he\she needs proper guidance for their aspired goal. But this doesa not take place at right time and continued the backwardness among this category. Somewhere or the other they may have in mind that their parents are labor, farmer, and uneducated and they must support the family in earning after completing school education. The environment of the education is not in the tradition of family, so their parents

also not feel the requirement of these kinds of environment. Due to these various reasons they may not set their aspirations for future. So, it's important to look deep at those sections which are deprived in nature, struggling for employment and living a segregated dignified life. In our society it needs to create an equitable society where no one lags just for not taking admission in English medium schools or not knowing English properly.

STUDENT POLITICS IN UNIVERISTIES: SHOULD IT BANNED?

Anurag Kumar

MA Sociology, Jamia Millia Islamia, New Delhi

E-mail: akambitiousguy@gmail.com

India has a long tradition of student politics, from the days of the young Bengal movement; students have played an important role in bringing social change. Student activism leading to student politics has played a significant role in the pre-independent era like the non-cooperation movement quit India's movement. Even in the post-independent era, student politics have led to a significant impact by their participation in major events like JP movement, emergency period, IAC (India's against corruption), justice for Nirbhaya, etc.

Student protest and agitation from various universitiesa have catalyzed the political turbulence across the nation. In the last few years, student politics in various universitiesa have taken a new form of protest by disrupting academic discourse, violence in the campus for their demands .due to this form of agitation, an image of the universitiesa have also been suffered, due to which large section of the population in our country demands to ban the politics in universities, as they argue that students should not be involved in politics at educational universitiesa and confined themselvesa to their respective academic discourse.

The paper will analyze the perspective of student politics and its relevance in the contemporary era, is there any need for banning student politics in universities. The paper would be based on the personal experience seen in universitiesa like JNU, DU. The author has done extensive study and the paper is based upon the opinion of literature, articlesa of multiple scholars on a similar subject. The paper would also highlight the impact of politics in education.

India is still laggard in Higher Education: An Analysis

Vivek Kumar
Ph.D Scholar (NET), Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi
E-mail: vlahaudda@gmail.com

India's Position in Higher Education is not satisfactory even though India is a developing power in Economic field. Looking at India Economic position it should be a leading country in the field of Higher Education. We can reach on this observation by looking at certain factors. In respect of Institutional density India is performing well in some statesa while lagging behind in majority of states. If we consider Gross Enrollment Ratio in Higher Education, we find that it is increasing with a very small margin. In case of pupil teacher ratio India's position is abysmal. Even it is a worse than that of other developing countriesa who are far behind India in other socio-economic factors. Another observation in Higher Education with respect to the Enrollment ratio of foreign students in India's Higher Educational Institutions is not of that range which is expected looking at its ancient and medieval past when India was a center of learning Institutions looks like Nalanda vihar, Takshila and Vikramshila etc. So India is expected to reach that level which it had in the past.

Educational Status and Challenges in Ladakh Union Territory

Bashir Ahmad
Research Fellow, Central Institute of Education, University of Delhi, Delhi
E-mail: bashirhmd369@gmail.com

To bring positive change in society and nation, education especially higher education is the strong agent. In higher education, after independence, India shows tremendous improvement and growth in terms of human and material resources. But the scenario of higher education in rural areas is still an extremely serious concern for the authorities. Ladakh 80 per cent of its population is tribal, situated in northern India, recently bifurcated from the state of Jammu and Kashmir and declared a Union Territory. Till date education particularly higher education is the untouched layer need to study in the region. Up to 1994, Ladakh was not even a single higher educational institution. In the last two decades, the data shows that Ladakh drastically improved their schooling education but higher education is still in the pathetic condition.

The present study examinesa the current status and challengesa of education in the Ladakh Union Territory. The data was collected by using different secondary sources.
Key words: Higher Education, Challenges, Ladakh

Mentor Teachers: An Innovation in Delhi Education

Vikas Drall

Mentor Teacher, Directorate of Education, Delhi Government, Delhi

E-mail: vikasdrall.delhimt@gmail.com

Innovation is the key to success. The same becomesa more crucial when it comesa to education. Innovation in education encouragesa teachers and students to explore, research and use all the tools to uncover something new. It involvesa a different way of looking at problems and solving them. The thinking process that goesa into it will help students and teachers to develop their creativity and their problem-solving skills. The introduction of mentor teacher program in Delhi is one such innovation in education that changed the whole outlook.

The mentoring process providesa a framework for each teacher to feel comfortable and confident to fully develop potential in the classroom. In long-run it infusesa professional development into a teacher. And it will not be wrong to said that professional development transform teachers into better and more apt educators by enabling them to create relevant and tailored course instructions for today's students. Mentorship program, introduced by the Delhi government, includesa continuous reflection on professional practice. Reflection is enhanced when approached as a shared dialogue among colleagues.

The mentor teacher program in Delhi providesa opportunity for teachers, including the new ones, to meet weekly with a mentor to engage in reflective dialogue. The mentorship program adopted a world class model of mentoring to promote questioning, dialogue and collaboration between a mentor and a teacher. The mentor teacher pairing is a non-evaluative relationship to examine and understand learning community, knowledge of learners, learning reflection process, instructional strategies, knowledge of self and professional responsibility as a contributor to the community. In a nutshell, mentoring process encourage teachers, motivatesa them, address them, providesa on-site support and refine them pedagogically.

The mentorship program promotesa sharing of acquired skills between a mentor and a teacher and vice versa, ultimately carrying an aim of uplifting the Delhi education. This is an innovation cum education revolution heading towards a better future for the students of Delhi government schools.

Mapping and Analysis of the Educational Status of Haryana

Ashwani
Research Scholar, Department of Geography, Delhi School of Economics, University of Delhi

India has the world's second-largest educational system. The Indian educational system has seen significant changes. A lot of work has gone into shaping the current educational system. The announcements included the elimination of mandatory CBSE board examinations for class 10th beginning in the 2010-11 school year, the implementation of a grading system, after the passage of the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. Haryana is the state that contributes 3.7 percent of India's overall GDP. The purpose of this research is to shed light on Haryana's educational system, as well as to examine several other sectors. This document is both qualitative and quantitative in character, and it is based on information gathered from several government websites as well as reports from the Planning Commission, the Government of Haryana, and the Government of India. All the districts of the region are divided into three categories on the basis of composite index of each of the district. Districts having highest composite index are Karnal and Yamuna Nagar while the Panchkula has lowest composite index. Rest of the districts depicts moderate picture. Ambala and Kaithal region have higher composite index as these districts are more urbanized and people of these districts are more education conscious.

Keywords: Education, Location quotient, Haryana, and Literacy Rate

Social, Philosophical and Psychological Status of Teachers in Ideologically Inspired Schools

Chetana Shakya
Research Scholar, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
E-mail: chetna.shakya22@gmail.com

Ideology is a set of ‘ideas’ used by a particular group as reflecting certain realities, aimed to justify or denounce a particular way of social, political, or economic reality. It is commonly accepted that schools inculcate ideologiesa and ideology they are following and have a direct influence on curriculum, pedagogy, administrative structure, etc. Usually, these ideologically inspired schools are opposing the conventional method of teaching and adopting the alternative method of schooling. Vidya Bharti Akhil Bhartiya Shiksha Sansthan is the educational branch of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) so, the ideology of RSS has a direct influence on the ideology of school. They believe in “One nation, one people, one culture” and the nation of ‘Hindutva’. This study is to understand the position of teachers in ideologically inspired schools where they are following a particular ideology. In the education system teachers are at the front and center of what is happening in education as a domain. Be it curriculum, policy, school management or classroom process, teachers have a vital role in every aspect of school education. This study is also trying to explore the relationship between Hindu Nationalist ideology and practicesa that how the rhetoric of creation of ‘Hindu-Rashtra’ and ‘Hindutva’ is translated and implemented in pedagogy by teachers in schools of Vidya Bharti.

New Education Policy: A Path Way to Conducive Development

Vandana

Assistant Professor, N.A.S College, Department of Education, CCS University, Meerut

E-mail: vandanasingh7182@gmail.com

Education plays a very important role in our development. Government of India has also given education the utmost importance. From the independence onwards Government of India is working on different programme to address the problems of education. From time to time government came up with different education policiesa in 1968, 1986, POA-1992. Now the Government of India has come up with a National education policy to meet the challengesa which are continuously coming in front of us all. Governments want to fulfill population requirement with regards to quality education innovations and research. Governments in this policy want its youth to acquire those necessary skills and knowledge, which will serve to eliminate the shortagesa of man power in science technology, academics and industry. The basic idea behind this policy is to educate encourage and enlighten the youth of our country. This policy lays stress on making education affordable to all, to develop world class skilled workforce, to make education flexible so that it can serve the needs of the students as well as society. New education policy will led us towards holistic education, which will ensure literacy, life skills and employability. According to this policy Education will be life long, no student will end their educational pursuits, due to lack of funds.

Key words: Education Policy, Skilled workforce, Employability.

Privatisation Of Education: A Boon or A Bane?

Dr. Rahul Chimurkar

Assistant Professor, Department of Political Science, Deshbandhu College, University of Delhi, Delhi

E-mail : rahul.chimurkar@gmail.com

Education is vital to the human resourcesa development and empowerment in the stagesa of growth of a nation. In any education system, higher education encompassing Management, Engineering, Medicinesa etc., plays a major role in imparting knowledge, values, and developing skills and, in the process, increase the growth and productivity of the nation. While the Government is committed to providing primary education and certain facilities/subsidiesa for higher education, given the higher cost involved in the establishment of higher education institutes, we are witnessing the entry of private sector to run educational institutions. However, privatization of education in India has its own benefits and losses. We can observe two typesa of privatization in education sector: Privatization in public education and Privatization of Public Education. The former, also known as 'endogenous' privatization involvesa the importing of ideas, techniquesa and practicesa from the private sector in order to make the public sector more like businessesa and more business-like. The later, also known as 'exogenous' privatization involve the opening up of public education servicesa to private sector participation on a for-profit basis and using the private sector to design, manage or deliver aspects of public education. This paper providesa an overview of the debatesa around the privatization of education; it presents the arguments that have historically been laid out for and against this process, and problematizesa its effects on social inequality and the uneven distribution of educational opportunities. It is argued that privatization of education could help in enhancing the education system in India but it needs to be regulated by state. Commodification of education will not serve the long term interest of our country i.e to become a knowledge power.

New Education Policy and Integral Humanism: A Perspective Search

Rohit Bharti
PhD Scholar, Department of Social Work, University of Delhi, Delhi
Email : roheetbharti@gmail.com

"Western Science and the Western Ways of life are two different things. Whereas Western Science is Universal and must be absorbed by us if we wish to go forward, the same is not true about the Western Ways of life and values.

--- Pandit Deen Dayal Upadhyay Ji

Education policy is foundation stone for society, state and country to let its people grow in direction fabricated, modelled in policy document. It's a blue print for future mankind and a policy statement to demonstrate its contribution in sustainable development. Education policy even contains catalyst variablesa in shaping ideology vice versa.

Paper is about deep reflection over new education policy through ideological perspective of integral humanism of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Integral humanism is about each and every action an individual takesa putting at the middle of whole universe, considering its own action effect on global ecological system. Pandit Deen Dayal Uapdhyay categorized human needs in four parts Body, Mind, Intellect and Soul which precisely would be looked after in process to achieve maximum glory of human being.

Method of data collection contains intensive review and reflection on secondary sourcesa of documents. Also, interview of educationist, scholars, practitioners included in methodology of collecting data through non probability purposive sampling.

Key Words: Education, Integral Humanism, Education Policy, Bharat

Use of ICT (Information and Communication Technology) tools in Government and Private aided Secondary schools of North Garo Hills, Meghalaya

Prasanna M Sangma
PhD Scholar, School of Education, Tata Institute of Social Science Mumbai
E-mail: mm2018edr001@tiss.edu

In India, ICT@school Scheme was launched in 2004 and was revised in 2010 to provide opportunitiesa to the secondary state students to mainly build their capacity on ICT skills and make them learn through computer aided learning process. ICT In schools has been subsuming in the RMSA and now ICT in schools is a component of the RMSA. ICT@School scheme is one of the computer aided learning scheme and is major catalyst to bridge the digital divide amongst students of various social, economic and geographical barriers and supports to states's schools to established computer lab on sustainable basis (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan).

In Meghalaya state, ICT training has been implementing under ICT@school scheme since 2008-09 and it was reported that 75 secondary and senior secondary schools have been covered under this scheme. In Dec. 2011, as per Directorate of School Education, Shillong, under ICT@school scheme, 241 schools from 7 districts are selected including government and government aided secondary and senior secondary schools; East Khasi Hills (63 schools), Jaintia Hills (24 schools), RiBhoi (14), West Khasi Hills (26 schools), East Garo Hills (21), South Garo Hills (15) and West Garo Hills (78 Schools). Under the Scheme, ICT Tools and training of teachers etc. are to be provided on Build- Own- Operate -Transfer BOOT basis. The objective of the Scheme was to established and promote the usage of ICT in all selected schools and develop and disseminate appropriate content in English. It is also involved capacity building of students including special needs in ICT and ICT enabled teaching and learning methods. In 2016, Government of Meghalaya proposesa again to expand the Scheme to an additional number of 67 secondary and Higher Secondary School.

As per DISE (Unified District Information System for Education) 2016-17 Report, in Meghalaya, there are 1629 total numbers of schools and out of which Secondary school report state that 16.64 percent of schools having Computer and internet facility.

North Garo Hills District is selected for my Research Studiesa and Schools that were actively using ICT tools for teaching purpose are selected and is purposefully Selected. Science, Maths and Social Science and English teachers are interviewed so as Headmaster and Principals of the Schools.

Teacher Education after Post-independence period in India: Issues and Remedial Measures

Jan Jahanger & Ishfaq Hussain Bhat

Research scholar, School of Education, DAVV, Indore, Madhya Pradesh

E-mail: janedu24.25@gmail.com

Mudasir Sadiq Dar

Research scholar, School of Social Science, DAVV, Indore, Madhya Pradesh

Education is the key for development of any country and it reliesa on the quality of teachers. Information, awareness, responsibility, quality, skills and creativeness of teachers are the elements liable for quality education and student accomplishment. Teachers are highly respected from the ancient time especially in India and thus have a significant task to carry out towards society. It is basic for them to be productive, talented, resourceful, principled and constant in the presentation of occupational duties. Efficient and cunning teacher education programs are required in the present world. Teacher education and training programs must be investigated, examined, transformed, reconsidered and reoriented in the present presence. It is crucial to formulate suitable measuresa and strategiesa that would upgrade teacher education and training programs. The students ought to be given suitable information and knowledge that would upgrade their scholarly ideas, yet in addition inculcate the qualitiesa of morality, ethics, norms and abilitiesa within them. The principle motivation of this research is to study the scenario of Teacher Education after Post-independence period in India. It highlights the reports of various commissions, committees, policiesa and programs which where framed from time to time for the effectiveness of teacher education as well as educators. This research also highlights the various issuesa which the teacher educators and education system are facing in todays scenario and lastly the various remedial measuresa were suggested for the betterment and efficient working of the teacher education system. This article will be valuable to a wide range of readers as well as policy makers who are struggling to retain competence and remain focused in the competitive academic world.

Keywords: Education System, Issues, Job Performance, Teacher Education, Teaching Skills

Role of Buddhist Concepts in the Development of Indian Education

Jyoti Dwivedi

Research Scholar, Department of Buddhist Studies, University of Delhi

In India during the time of Buddha, there was a racial discrimination in the society. This discrimination was according to profession of man and according to birth. In the society there were four divisions of whom Brahman was superior. They enjoyed rights for religious training and education. But other category of people deprived of their religious and educational rights.

It should be observed that it is "the life of holiness" which Buddhism emphasizesa much more than the philosophy of life, speculations concerning the mysteriesa of life and death and such ultimate truths. The entire system of Buddhist education must be rooted in faith (saddhā)-faith in the Triple Gem, and above all in the Buddha as the fully enlightened One, the peerless teacher and supreme guide to right living and right understanding. Based on this faith, the students must be inspired to become accomplished in virtue (sīla) by following the moral guidelinesa spelled out by the Five Precepts. Students should come to appreciate the positive virtuesa these precepts represent: kindness, honesty, purity, truthfulness, and mental sobriety. They must also acquire the spirit of generosity and self-sacrifice (cāga), so essential for overcoming selfishness, greed, and the narrow focus on self-advancement that dominatesa in present-day society.

In the early period Buddhist Education was limited within the monasteriesa and only for the members of the monastery. But later on it was open to the mass, even lay people got scope to have education in those institutions. In modern days Buddhist Education became wide open and embraced people of all walks of life. The aim of Buddhist Education is to change an unwise to wise, beast hood to Buddha hood.

Keywords: Triple gem, five precepts, Monasteries, Enlightened, and Buddhahood.

Use of Technology in Education

Manisha Jain

Research Scholar, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, U.P.

E-mail: mjjainmanisha@gmail.com

In today's era, the role of Technology is emerging in every sphere of life, whether it is Personal Identity Record Management, various household requirements such as: Gas, Water, Electricity etc., Transportation, Infrastructure, Agriculture, Hospitals, Banking and Investments, Defence or Education. In the above said fields, the use of technology is at its peak except in the field of Education. In educational institutions, the technology is not being optimally utilised, and in government educational institutions, thecondition is even worse. However, the government has taken several steps to increase the use of technology in the field of education, but these seem to be insufficient as there is still digital division among the population of the nation.

Use of technology in education works as a multiplier as the learning of students becomesa many timesa interesting. The main purpose of teaching is to create interest about the content to be taught, and use of technology is one of the most effective tools for that purpose. One of the main aims of education is to create knowledgeable, skilled and wise citizens. Technology not only makesa learning effective, it also cultivatesa the skills and proficiency among learners. The economy of the nation depends upon three sectors: Agriculture, Industry and Services. If the nation wants these sectors to develop, it definitely has to improve the skills of people engaged in these sectors. More than **65%** of all school children get their education from Government schools. Du e to decreasing quality of education and lack of use of Technology, the enrollment o f students in government institutions is decreasing. We have to take strong steps to use technology in education and to impart Technology based education to students of Bharat; to make Bharat dynamic, A daptive (to positive changes) and to ensure its I nclusive Growth.

Challenges and solutions of Primary, secondary and higher education in government sector institutes

Suman Sharma
Research Scholar, Central Institute of Education, University of Delhi, Delhi
Email : parashaar@gmail.com

Life can be defined as a struggle in form of a process. When a person, a society or a nation want to achieve a goal. Every one has to face problems and obstaclesa in it. Then everyone as per capacity and available resourcesa make stretegiesa for resolving the problems, get solutions and move forward in the process of life. Developments occure, changesa happens. It works just like a cycle as Aim or goal…. Processes…. Problems… and efforts and finally get solutions.

Let's first see the topic in depth. First word is challenges. Challengesa can be defined as problems, obstaclesa and questions etc. Second word is solutions. Solutions can be understood as purposely selected resourcesa for making or creating the new way or make the way easy. By which problems can remove and goal can achieve.

For knowing the challengesa and solutions of education field in government sector, we should have an overview for all over educational scenario of India. After this we are very much clear about the following points:

1. Available and non available resourcesa (Human resourcesa and physical resources).
2. Management and working skills of present stuff.
3. Ways, methods and technics of work.
4. Stretegiesa and updation of current scenario of demand and supply.
5. We must be aware and very much clear about the ultimate goal which we want to achieve.

We will understand this challengesa and solutions under the basis of the following points:

- Teachers
- Students
- Building of School.
- Curriculum
- Text Books
- Extra curricular activities.
- Exam and Evaluation patterns etc.

This paper is a keen effort for understanding the challengesa and solutions for various educational levels of government sector.

The scenario of Education in Rural areas of Assam

Surajit Gogoi
Lakhimpur, Assam
E-mail : gogoisurajitsg02@gmail.com

Education is one of the major reasons for the development of a society. One can achieve success in life through the education. Education doesn't only imply in formal ways but also in informal ways for the development of a person with the passage of time. The rural areas of Assam are getting the glimpse of education in a productive manner. Hence, the children from the rural areas have started to enrol in schools. Basically, the rural people are very poor and that is why they should get the knowledge of being educated. The Sarba Siksha Abhiyan has shown the progressive thought process among the schools with various projects along with the curriculum. A child should not limit himself/herself within the syllabus, but overall personality development can boost the better prospect of life. In Assam, the schools of rural areas need proper infrastructure with financial support. Then the education system will be gearing up in different ways. The children should get the motivation through their curriculum. Flood is considered to be one of the major natural calamitiesa of Assam. Flood ruins and destroys many villages schools' area, road and bridges. Due to this problem, the children cannot study with the focused required of them. There only liesa with two options during the flood time whether they should opt for food to fulfil their hunger or education. By that time, the children engage in different kind of works and leave the school. We should rectify it in a methodical way to engage them in studiesa again. The government should give the importance of quality of education rather than focusing on quality only.

Status of Education in Slum Area

Manu Kajla
Research Scholar, S.M. JN P.G College, Haridwar
E-mail: manukajla999@gmail.com

Education plays a vital role in overall growth of any Country. With increasing urbanization, urban migration has led to a serious problem of increase in urban slums. These urban poor usually consist of semi-skilled or unskilled labor. The poor condition of these urban poor in slum areas is mainly due to their inability to compete with skilled labor class and afford a decent standard of living. The role of education in improving the socio-economic conditions of slums in India. The educational level of Slum residents in India is very low and there is an urgent need to improve the educational attainment level of Urban poor for better economic growth. Various schemesa have been introduced by government in this regard. However, only few of them have been successful. This paper is a descriptive analysis of the role of education in improving the conditions of urban poor. Educating the semi-skilled and unskilled labor is the need of the hour.

Secondary Education in India: Issues and Concerns

Dr. Krishna Kumar Pandey

Assistant Professor, Department of Education, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G).

E-mail- *krishna.cvru@gmail.com*

Secondary education serves as a link between the elementary and higher education, and plays a very important role in this respect. A child's future can depend a lot on the type of education she/he receives at the secondary level. Apart from grounding the roots of education of a child, secondary education can be instrumental in shaping and directing the child to a bright future. This stage of education serves to move on higher secondary stage as well as to provide generic competencies that cut across various domains of knowledge as well as skills. The recent significant development of society, impact of globalisation and rapid growth of new technologies have led to reassessment of India's preparedness to generate required technical manpower, develop new knowledge and skills, and remain competitive at global level. Since free and compulsory education to all children up to the age fourteen is the Constitutional commitment in India, all efforts in the past were focused on achieving the goal of universal elementary education. It is upper primary and secondary level of education that is now in the focus. Over time, secondary schooling facilities improved to a significant level but still there are a few areas of concern like Schooling facilities to a large number of habitations were not available. Government schools had lower percentage of buildings than the schools under the private managements. So far as the investment on education is considered, secondary education has never been the priority area of investment. In order to meet the challenge of Universalisation of Secondary Education, there is a need for a paradigm shift in the conceptual design of secondary education. The guiding principles in this regard are; Universal Access, Equality and Social Justice, Relevance and Development and Curricular and Structural Aspects. Universalisation of Secondary Education gives opportunity, to move towards equity. The concept of 'common school' will be encouraged. If these values are to be established in the system, all types of schools, including unaided private schools will also contribute towards Universalisation of Secondary Education by ensuring adequate enrolments for the children from under privileged society and the children Below Poverty Line families.

Validation of Engineering Self-Efficacy Scale using Mokken Analysis in Indian Context

Jaspreet Kaur

Student, School of Education, Lovely Professional University, Phagwara, Punjab

Dr. Rajib Chakraborty

Associate Professor, School of Education, Lovely Professional University, Phagwara, Punjab

The study was conducted to validate the Engineering Self-Efficacy scale, originally was developed by Mamaril et al., (2016) which measures the General engineering self-efficacy of engineering students using its 6 items. The study was conducted on a sample of 200 second year engineering undergraduate students of Lovely Professional University, Phagwara, India belonging to Computer Science, Mechanical, and Electronics Engineering steams. In this current research, the non-parametric technique of Mokken Scale Analysis was used to validate the tool, with the help of R/RStudio package "*mokken*". In the results, the automated item selection procedure produced coefficients which were greater than 0.3 for all the six items individually indicating their belonging to a uni dimensional construct. The monotonicity plots of all the items displayed the desirable rise in the latent trait for the increase in the scale's responses. The Mokken scale reliability coefficient was found to be quite acceptable at 0.823. Also, the conventional estimates of internal consistency reliability Cronbach alpha, and Guttman Lambda 2, were found to be also acceptable at 0.815 and 0.818 respectively. The advantage of the usage of non parametric Mokken scale Analysis based uni-dimensional scale validation over the established parametric methods of tool validation through structural equation modelling based Exploratory factor analysis and Confirmatory Factor Analysis are discussed along with the study's educational implications on engineering students.

Keywords: Engineering Self-Efficacy Scale, Mokken Scale Analysis, Engineering Undergraduates, General Engineering Self-Efficacy, mokken package

Indian Higher Education: Contemporary Challenges and Suggestions

Dr. Kiran Garg
Assistant Professor, B.Ed. Department, Digamber Jain College, Baraut, U.P.

Mrs. Sushma singh
Assistant Professor, B.Ed. Department, S.B.D.P.G. College, Dhampur, U.P.

Education is a Nation's Strength. A developed nation is inevitably an educated nation. Indian higher education system is the third largest in the world, next to the United States and China. India has a long history of higher education, which is evident from the fact that India was one of the first countries in the world to establish a university. It created a demand for higher education as well as graduates. Despite this rich past, India has not been able to develop world-class universities, and its students are not adequately prepared for such an opportunity. Since independence, India as a developing nation is contentiously progressing in the education field. Although there have been lot of challenges to higher education system of India but equally have lot of opportunities to overcome these challenges and to make higher education system much better. India need well skilled and highly educated people who can drive our economy forward. India provides highly skilled people to other countries therefore; it is very easy for India to transfer our country from a developing nation to a developed nation. The present study aims to highlight the challenges and to point out the suggestions in higher education system in Inda.

Keywords: Education, Higher Education System, Opportunities, Challenges, Suggestions, Colleges, Universities.

A concept of interrelation between Mathematics and Physical Education

Dr Anil Kumar
Associate Professor, Dept. of Mathematics, MMH College, Ghaziabad

Mathematics is no more tedious and difficult. Its creativity can be appreciated through classroom activities, mathematical patterns, mathematical games, mathematical puzzles, mathematical paper folding, magic squares, etc. In mathematics, each and every step we move ahead is explained through inductive reasoning or deductive reasoning.

Mathematics is used to keep track of a person's fitness progress and results, and also to measure, analyse, compare, and enhance the performance of an athlete on and off the field. Mathematics and Physical Education have common ground and fundamental links that underpin these two.

In this paper, there are many effective and creative ways to understand the link between mathematics and physical education.

Public Expenditure on Elementary Education and Educational Attainment in India

Amritpal Singh Kalsi
Research Scholar, Lovely Professional University, Punjab

Dr. Tushinder Preet Kaur
Professor, Lovely Professional University, Punjab

Education is a fundamental pillar of human evolution and development. It can be considered a potent tool that can change people, nations, and the world community. Education transforms people with skills and information that make them able to accomplish their goals, with the help of educated decisions, which ultimately impact society. Elementary education is the first and foremost phase of formal education that begins at the age of 5 or 6 with preschool education that starts early at age of 3. The potential objectives of elementary education are the same around the world despite cultural, demographic, and political differences among the countries because it lays the foundation for building a stronger society. Public spending plays important role in the promotion of elementary education with its goal of universalization of education. This paper tries to examine the link between public expenditure on elementary education and educational attainment in India. While enrolment is the level of schooling at a particular period being attended by children of a certain age group, educational attainment is a far more crucial aspect of educational outcome that refers to the level of education that a person has completed. The study is based on secondary data, the data has been taken from ministry of education reports and various documents, reports, and publications, the Annual Status of Education Report (ASER). The period for the study has been taken from 2011 to 2020. The study shows that public expenditure on elementary education has increased significantly and there is a positive trend in educational attainment with a lesser number of students dropping out of school and a considerable number of children completing elementary education, which is a positive step toward the development of human capital in the country.

Keywords: Elementary Education, Public Expenditure, Educational Attainment

Study of Self-Esteem on the Two Genders of Secondary School: Boys and Girls

Tapasaya Raj Mukker
Research Scholar, Department of Education, Shobhit Institute of Engineering and Technology, Meerut
Email: tapasyagupta001@gmail.com

"*Being worthy is not something you earn. It is something you recognize and believe in."* ~ **Invajy**

The times are changing and with it is changing the world around and its generation. Children of today are the future of tomorrow and each child is important in his or her own way. The world is now a competitive one and in order to see oneself achieving something in life they must be active and considerate towards their needs and life. Self-esteem is very important and needs to be developed in every child. In psychological world it means how much a person loves or appraises oneself. If you are happy and content then your self-esteem will automatically be high and in your favour, but if factors such as family, friends, finances, surroundings are influencing you then your self-esteem won't be on the higher side of scale but will stoop and the child looses confidence. Number of times it's seen that the financial status or the academic achievement of a student leads to his high or low self- esteem. The level of self-esteem should be developed in an equal manner for all the students. Self-esteem highly affects the behaviour and thought process of a child. For a healthy life we must develop positive self-esteem and learn to value ourselves. This needs to be taught to the children at a very young age so that later life and situations are easy to tackle. Secondary school students are at a stage where they are at the threshold of adulthood. So, they need to be very efficient and should know how to handle things smartly. Life gets more sorted when the beginning days are well trained and motivated. If at this stage through good guidance and motivation the students are brought up and educated, then their personal and professional lives will surely enhance. High self-esteem leads to a positive student life. The present study aims to examine self-esteem among boys and girls of Secondary schools. Dr. Santosh Dhar & Dr. Upinder Dhar's Self Esteem Scale (SES) developed is used to measure self-esteem of the students. The study comprised a small sample of 30 boy and 30 girls' students' of class IX of Secondary school of District Haridwar, Uttrakhand.

Education For Happiness: A New Approach of Teaching-Learning

Dr. Narendra Kumar
Assistant Professor, Department of Education, Central University of Rajasthan
Dr. Rajive Kumar
Associate Professor, Department of Education, N.A.S. College, Meerut

Happiness is a special term that is a quest and required by every human being since the beginning of human civilization. Everyone needs happiness in their life regardless of their gender, religion, socio-cultural or socio-economic background. During the COVID pandemic, people were advised to be happy and stay safe and healthy rather than being famous or rich. Thus, balanced, positive, pleasant emotions with all joy, gratitude, and pride lead to living a happy life. Happiness can be defined as a person's physical, emotional, and mental state with a collection of bunches of positive and pleasant emotions being enlightened oneself. The common ingredients of happiness include running behind the truth and self-control, belief in oneself, complete realization of victory-defeat, gain-loss, pleasure-pain, etc., fighting for own welfare and others, searching for integrity and disciplined life, surrendering ego, violence, and humility, etc. It has been proved that a happy man is the healthier one. Thus, to become healthy, a person must be satisfied; to become happy, he must enjoy his life; to enjoy life, he must earn money. However, money can't buy happiness. Happiness plays the most vital role in students' life. In order to develop the nation, the pillars of the nation must be developed; for the development of pillars, i.e., the students, their psychological and emotional development must be balanced; for balancing the emotion, the happiness factor must be developed among them. This rapid and complex changes in society, technology and science bring this generation to deal with much stress. Students are forced to run behind the advancement and achieve the success in order to establish themselves as a renowned and respected person in the whole world. In order to achieve their goal, they are taught with high achievement motivation; grasping those motivations and working upon them with the feeling of anxiety, they find themselves more competitive. In order to perform well in the academics, students must be happy as happiness is directly correlated with the academic achievement. When a person is happy, he is better able to solve any problem, so is the student. When students are asked to solve a question related to critical thinking, they are more exposed to develop their cognitive and reasoning abilities. When they try to bring creativity into their solution, they are more diversifying at that time. Various researches were done to study the relationship between happiness and academic achievement of students. The results of the study found that the students experiencing better well-being had been a member of pro-social orientation program. Also, the studies found there was an important and significant relationship between students' happiness and their academic achievement. Thus, students are advised to develop their physiological well-being thereby developing their happiness. To build a bright and fruitful future, and to enrich an amazing personality, there is greater need for the fulfillment of fundamental demand i.e., happiness, for every student.

Women Disability: Existing challenges and Future Possibilities to stir up their voices for justice

[1]Ms. Monika
[2]Ms. Sonali Sambyal
[3]Dr. Kiran
[1]Research Scholar, Department of Educational Studies, Central University of Jammu
[2]Research Scholar, Department of Educational Studies, Central University of Jammu
[3]Assistant professor, Department of Educational Studies, Central University of Jammu
Email: mb60206@gmail.com

Gender equality and women empowerment are critical to achieve internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals. Women and girls with disabilities face double discrimination, increasing their vulnerability to gender-based violence, sexual abuse, neglect, maltreatment, and exploitation. Due to the existed subtlety regarding gender disparities in society, array of unbalanced responses towards equality. Equality for woman is emerging as, the most pressing issues of the 21st century**.** Their position has gradually changed since the beginning of the twentieth century. Even, in present their decision-making power at home and freedom of movement vary greatly depending on their age, education, and employment status. It has been discovered that women's acceptance of unequal sex norms is still prevalent in society. Women with disabilities are completely ignored and left in a pitiful state. The society always downplays their abilities, and as a result, they are not considered a part of society, and there are not enough opportunities provided for their true realisation. Women with disabilities continue to face significant challenges in obtaining an education and fair treatment. To gain access to public funds, appropriate policies and their proper implementation are required. To support and encourage these women, full participation in social and public life is required. So, there is need to assist women with disabilities and to achieve their full participation depends upon positive and constructive attitudes of the society. The purpose of this paper is to examine the status of women in India and shed light on its problems and challenges and suggesting some ways of empowering them.

Keywords: Disability, Women, Status, Challenges, Possibilities

An Overview of New Education Policy 2020

Nilofar Anjum Siddiqui
New Delhi
E-mail: nilofarsiddiqui02@gmail.com

For every country education is the key driver for the economic and social progress and a policy establishes broad objectives and suggests a course of action. It provides guidance and frameworks for developing a road map toward goals. The National Education Policy has outlined a grand vision for what Indian education should look like over the course of the next 50 years.

The four pillars of Access, Equity, Quality, and Accountability form the foundation of the new NEP. The NEP is a ground-breaking initiative that has given research using paradigms in the nation's higher education sector a new dimension. With this, the policy's intentions are made very clear, calling for universities in particular to revive the research culture and transform into hubs for knowledge creation. But it must be kept in mind that success depends entirely on strict adherence to the policy provisions rather than limiting itself to being a simple policy statement. This paper aims to identify the concern and focus of NEP 2020.

Keywords: New Education Policy, higher education, guidance, framework, knowledge creation, concern.

Contribution of Dr. B.R. Ambedkar to Indian Education and Society

Dr. Ravikant
Assistant Professor, Department of Chemistry, Zakir Hussain College, Delhi

Education aims at bringing social, economic and political change in people's attitude. Dr. B. R. Ambedkar, with his experiences in Indian society, was a staunch opponent of social discrimination, casteism, gender inequality, untouchability etc. According to Dr. Ambedkar education is the only tool to bring structural changes to Indian Society and it would eliminate the existing gender and social inequalities and establish a sense of brotherhood and mutual respect. In his words, "Education is not only the birthright of every human being but also a weapon of social change" He **focused on making education free and compulsory by incorporating article 45**. He also emphasized women education and education that builds the character of individuals. Ambedkar's philosophy is influenced by societal problems that he faced.

KEYWORDS: Education; Dalit; Ambedkar; empowerment; Indian Society.

The Vedic Education System: Present Relevance

Dr Pragyan Dangwal

Amity University, Uttar Pradesh

Modern Education is the latest and contemporary version of education that is taught in schools and learning institutions in the 21st century. It not only focuses on prominent academic disciplines but also aims to foster critical thinking, life skills, value education, analytical skills and decision-making skills in students making use of the latest technology to educate learners and make the learning process more engaging and interesting. Modern or traditional, we cannot categorise education as good or bad. The education system has evolved over the centuries; however, for a forward thinking nation with a higher level of education than anywhere else during the ancient times would definitely merit some relevance in today's times too. The present study looks into those aspects of the vedic education system which have relevance in today's modern education system and would fulfil the goals of NEP 2020. According to Rabindranath Tagore, the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. Through vedic ideals we can bring certain desirable changes in the students. In Ancient India the ideal of life was spiritualistic. Educational aim was determined by the conception of life. Thus the aim of education was self-realization or the realization of Brahma or the Absolute. The Vedic system of education was aimed at moulding the young minds into individuals capable of living a perfect and full life based on the principles of Dharma. The educated ones in that system were men who had not only knowledge but also character. According to the Upanishads. education is that whose end product is salvation. Education according to Indian tradition is not merely a means of earning a living; nor it is only a nursery of thought or a school for citizenship. It is initiation into human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue. The ancient schools followed the principle of education for self sufficiency. The modern education system like the Vedic education system ought to work towards preserving and spreading its culture and literature and reviving the ancient practices of positive approach towards diversity, inclusion, compassion, a sense of responsibility towards the universe and imbibing the philosophy of vasudhaiva kutumbakam.

Keywords: Vedic education system, modern education system, value education, character building

Universal Design of Learning: Critical Analysis with Reference to NEP 2020

Ms. Preksha
Junior Research Fellow, Department of Education, P.U., Chandigarh

Universal Design for Learning (UDL) is an instructional design framework that takes into account the wide range of variations in skills and abilities that exist across all learners, and provides a research-based set of principles and guidelines for inclusive curriculum development and delivery. This review presents the Universal Design Learning (UDL) approach to education. Classrooms have become increasingly diverse, with second language learners, students with disabilities, and students with differences in their perception and understanding information. Some students learn best through listening, while others learn best when presented with visual information. Given the increased number of new language learners across the world, the UDL approach allows successful learning for all students. UDL has allowed students to acquire information more effectively. UDL provides guidance to educators that is especially valuable for the diversity of classrooms and the diversity in modalities in learning. This article proposes the application of the principles of Universal Design for Learning (UDL) as a framework for promoting inclusion in outdoor learning in which students with and without disabilities learn and gain knowledge. The authors conceptualize outdoor learning, highlighting the potential for more child-initiated experiential learning. Yet this paper is not concerned only with outdoor learning, but with the inclusion of all learners in outdoor learning, through enactment of the curriculum in mainstream schooling. The diverse profile of children in schools calls on teachers to prepare teaching, learning and assessment activities to address a wide range of social, emotional, physical, cognitive and cultural needs. Contemporary researchers recognize outdoor learning as an effective pedagogy to promote inclusion and therefore reduce the barriers for full participation in the primary classroom. UDL is offered as a framework for planning outdoor learning to support delivery of curricula that are responsive to the needs of all learners. UDL is underpinned by three principles: multiple means of engagement, representation, expression and action.

Keywords: Universal Design for Learning (UDL), Inclusive Education

Art of Educating Children with Autism and Similar Disorder

Priyanka Tripathi
Research Scholar, Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh

Autism is a neurological ailment that lasts a lifetime, a developmental problem that usually manifests itself during the first three years of life. Autism manifests as developmental deficits in three areas: communication (verbal and nonverbal), social relationships, and imagination, which can be observed in repetitive and restricted play or leisure activities. This is known as the trinity of deficits. While these areas frequently emerge late, what is more important is that they develop in unexpected ways. Many people with autism have diverse ways of 'sensing' their surroundings. Some people, for example, may dislike being handled gently and prefer a hard grip. Others may find it difficult to brush their teeth or get a haircut. Many people will find it difficult to tolerate some ordinary sounds. Autism is not an uncommon or rare disorder. It is the third most common developmental disability, after Down syndrome and Autism. Professionals are beginning to grasp that some persons who were diagnosed with mental retardation, hyperactivity, or labeled as misbehaving children may truly have autism as understanding and awareness levels rise.

Key words: Autism, Its similar disorder, its education

Research on Teaching Leadership, Curriculum development, and effective pedagogy

Dr. Kiran Garg
Assistant Professor, B.Ed. Department, D.J. College, Baraut

Sapna Kumari
Research Scholar, B.Ed. Department, D.J. College, Baraut

Leadership, Curriculum and pedagogy are the vital components of an effective teaching . in the recent years, demand for effective leadership, better curriculum and innovative pedagogy have been increasing significantly for copying with the demands of challenging world and education . It is still an open space for debates and improvements about the best ways schools and universities can approach in a more creative and innovative way such development targets. In this study the aim is to describe the researches and innovation has been conducted in leadership, curriculum development and pedagogy.

Key words- curriculum development, innovative pedagogy, teaching leadership, learning, teaching, research etc.

Focus of NEP 2020 on Usage of Technology: Exploring the Scope and Future Pathway

Reecha Jrall
Research Scholar, Department of Educational Studies, Central University of Jammu, Email – reechajrall@gmail.com
Dr. Kiran
Assistant Professor, Department of Educational Studies, Central University Of Jammu, Email-Kirannmrc@Gmail.Com

We have entered into an era where convergence of emerging communications and information technologies is taking place. To compete and survive in the competitive world of education it is essential to create, adopt and use new educational technologies. Indian companies contribute significantly to the advancement of information and communication technology as well as other cutting-edge domains such as space. A digitally empowered society and knowledge economy is being built throughout the nation through the Digital India Campaign. Technology is emphasized in NEP 2020 to improve education in multiple areas and to increase transparency, rigor, and rigor in educational processes in general. NEP 2020, emphasizes use and integration of technology to improve multiple aspects of education also for ensuring rigor and transparency in educational process including scaling them up. The NEP 2020 proposes for complete revamping of teaching learning process. It also mentioned that teacher must be trained in such a way so that they can efficiently able to create, design and develop e-content for teaching and learning and an automous body NEFT (National education technology forum) Platform for the free exchange of ideas relating to the use of technology for enhancing school and higher education learning, assessment, planning, and administration. Traditional physical classroom teaching is totally flipped to technology integrated or virtual learning and this shift is need of an hour that reconstructs the whole process of teaching and learning from teaching to evaluation. E learning strategies such as, blended learning, online teaching and learning tools and virtual labs creation is the main highlight of NEP 2020. As a National Assessment Center or PARAKH, School Boards, NTA, and other identified bodies, we have developed a framework for assessment, which is very different from the traditional assessment and evaluation. This framework includes competencies, portfolios, rubrics, standardized tests, and assessments analytics. In the backdrop, the present paper intends to explore the technological framework proposed in NEP 2020, with reflecting on how the proposals shall be changing the directions of educational discourse in future.

Keywords- E - Learning, NEP 2020, NEFT, PARAKH, Blended Learning, E-content

Status on Implementation and Challenges of Early Childhood Care and Education in India

Sonalika Biswal
Research Scholar, P.G. Department of Education, Rama Devi Women's University, Bhubaneswar, Odisha

India has notably implemented one of the world's largest comprehensive ECCE programmes fairly early on, in the 1970s - the Integrated Child Development Scheme (ICDS). However, health, nutrition and education- related indicators of child development for 0-6 year olds, though having improved over the years, remain far from satisfactory. Despite the centrally sponsored ICDS scheme having been universalized, around half of India's under-six population does not participate in any form of pre-primary education. The lack of a regulatory framework for the rapidly expanding private sector, the second largest provider of ECCE, raises matters of concern around quality and equity. There have been several government policies and frameworks reaffirming commitment to developmentally appropriate ECCE services. This paper aims to reflect on the status and Gaps in ECCE in India.

Key Words: Challenges, Early Childhood Care and Education, Policy Frameworks and Status.

Psychological Capacity Building in Teachers

Dr. Soni Kewalramani
Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh

Teachers are truly the builder of the nation as all other professions are built through them. They have one of the most challenging tasks – guiding the young minds towards their profession and also inculcating professional and human values. The emotional, mental and spiritual rejuvenation and capacity building is a task which has a prominent place in the life of a teacher. In India, the need for training and capacity building is even more due to teacher – student ratio. Capacity building leads to innovative ways to deal with the challenges which teachers face in Indian scenario. In India, mental health is still a taboo and talking and working on psychological capacity building is even less. Emotional well-being, development of attitudes and skills to deal with disruptive behaviour, recognition of stress, depression and suicidal tendencies in students and understanding their own burn-out stage, resilience building, relationship with family and colleagues, anxiety over grades in students, bullying behaviour, daling with online world- social media and online education – both for students and teachers are some of the topics which are needed to be covered under Psychological Capacity Building of students. The present paper is an attempt to discuss its importance and implication in education.

Key words- Psychological Capacity Building, Teachers, Need, Emotional well-being

Prospects and Challenges of Learning Management System in Higher Education

Subhashree Panda
Research Scholar, Rama Devi Women's University, Bhubaneswar

The present age is the age dominated by the digital technology. Many Higher Education institutions now-a-days are equipped with Learning Management System (LMS) to provide rich online learning solutions and utilize its functions and capabilities to improve the learning Practices. Learning management systems (LMSs) is a software application designed specifically for online learning. It is used for administering, documenting, tracking, reporting, automating, and delivering educational programmes. The purpose of this study is to explore the instructor's perspective and identify the challenges of using LMS in Higher Education.

Keywords: Learning Management System, LMS, Online Learning, Digital Technology, Higher Education, Perspective, Challenges.

The Positive Effects of Technology on Teaching

Mrs. Aapurva Goel
Assistant Professor, Department of Commerce, IIMT University, Meerut

Mr. Puneet Kumar
Assistant Professor, Department of Commerce, IIMT University, Meerut

Technology in the current scenario is becoming noteworthy than ever and is also becoming a new reality for learning and teaching processes. With the Covid-19 pandemic affecting people and overall economic activities around the world, technology has played a major role in revival of people from the lockdown scenarios disrupting academics. Distances are no longer an impediment to education, and it is now available to students on a daily basis. Today, more than ever, educational institutions are engaging virtually with teachers and students with use of Information and Communication technologies (ICTs). It is now being referred to as educational technology. The major role that education technology plays is improving communication among peers, which facilitates the transfer of skills and knowledge to students and also improves the quality of study time.

Apart from this, E-learning tools and numerous applications such as Microsoft teams, Google meet, EdTech etc helps students to connect virtually and access information required from anywhere anytime. Even several government initiatives at the primary level namely development of computer labs is enhancing the focus towards education technology. Education Technology is thus a process of utilizing modern technology for improving quality education. The study is a hypothetical effort to investigate the functions of modern technology in education compared to the time before the Covid-19 strike.

Incorporating Behavioural and Social Science Content in Education

Dr. Jyotsana Shukla

Assistant Professor (Grade III), Amity Institute of Behavioral and Allied Sciences, Amity University Lucknow Campus, Uttar Pradesh

Behavioral science is somewhat new to education. Behavioral science has been applied too healthcare settings for behavioral change. Can it be applied to behavior change in education? The answer is yes. As in both the settings individuals are working towards goals. In education, the goals are e.g. better grades and thinking better or studying better. People might be taking different actions to these goals, but the fact that motivation is required to take action remains the same for all. The patients in health settings as well as the learner in education need self management skills and motivation and many other behavioral skills to reach their goals. Hence, there is a need to incorporate Behavioral and Social science Content in all curricula. There are a number of challenges that come in the way of accomplishing this objective, such as, resistance form poorly informed faculty members about the relevance of these courses, and form the administrators. Other issues include lack of resources to support the faculty, the curriculum development of such content, and the lack of availability of the relevant faculty members to teach these courses.

These challenges and many others will be discussed in this paper. There are various ways to surmount these barriers. The paper will delve on many ways to overcome these barriers from the author's own experience of working in setting where the behavioral and social science content is an integral part of the curriculum for many years and has helped many students in their career path. Some of these observations can guide the development of curriculum in government education and help them the goal of making the behavioral and social science content a part and parcel of their education system.

प्राचीन भारत में नारी शिक्षा – एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. रेखा राजपूत

कन्या गुरूकुल परिसर, देहरादून, उत्तराखंड

E-mail : rathorerekha483@gmail.com

भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से ही शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया तथा भौतिक, आध्यात्मिक उत्थान एवं विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए समय के साथ शिक्षा का विकास एवं विस्तार किया गया।

प्राचीन भारत में दीर्घकाल तक शिक्षा का तात्पर्य मुख्य रूप से वैदिक शिक्षा रहा जो बिना लिंग भेद के स्त्री–पुरूष दोनों को दी जाती थी। अनेक विदुषी एवं मंत्र द्रष्टी ऋषिकाओं के उल्लेख प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते है। ज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ किसी प्रकार पुरूषों से कम नही थी। अनेक स्त्रियाँ वैदिक शिक्षा के साथ गणित, वैद्यक, नृत्य–संगीत शिल्पादि, धर्नुवेद एवं युद्ध–विद्या की भी शिक्षा लेती थी। यही नही आवश्यकता होने पर वे युद्धों में भाग लेती थी। अनेक स्त्रियाँ अध्ययन–अध्यापन का कार्य करती थी। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में वे सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही थी।

परन्तु विचारणीय यह है कि प्रारम्भ से ही सैद्धान्तिक रूप से समान शैक्षिक एवं धार्मिक अधिकारों के बाद भी स्त्री एवं पुरुषों को दी जाने वाली शिक्षा में भेद था जो समय के साथ बढ़ता गया। कालान्तर में कर्मकाण्डों की जटिलता, ब्राह्मणों का वर्चस्व, सामाजिक पद–प्रतिष्ठा एवं अधिकारों के सन्दर्भ में नारी एवं पुरूष के बीच बढ़ती खाई इस बात की पुष्टि करती है कि स्त्रियों का शिक्षित होना ही अनिवार्यता नही थी। गृह कार्यों में निपुणता, सेवा भाव, समर्पण, सन्तानोत्पत्ति एवं उनका पालन स्त्रियों के महत्वपूर्ण कर्तव्य माने जाते थे। इस प्रकार स्त्री–पुरुष के बीच कार्य विभाजन ने स्त्रियों को गृह–संचालन एवं सन्तानोत्पत्ति तक सीमित कर दिया। यद्यपि उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियाँ सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थी। किन्तु सामान्य एवं निम्न परिवार की स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। यह बदलते हुए सामाजिक दृष्टिकोण का परिणाम है जिसमें स्त्री स्वतन्त्रता को बाधित करने एवं पुरुषों का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास देखा जा सकता है।

शिक्षा और उसके बदलते आयाम

डॉ. त्रिसुख सिंह

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज, सराहनपुर, उ. प्र.

E-mail : trisuk001@gmail.com

किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति की पहचान उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। क्योंकि शिक्षा ही नैतिकता, मूल्य, संस्कृति एवं आदर्श एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित किये जाते है। भारत की शिक्षा वैदिक शिक्षा पद्धति पर आधारित रही। जिसमें राज्य के युवा वर्ग को प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए तैयार किया जाता था। आचार्य की शिक्षा, पुरोहित वर्ग की शिक्षा, आत्मरक्षा, वेदों की शिक्षा, दर्शन, तर्कशास्त्र, अस्त्र–शस्त्र की शिक्षा, कास्तकारी एवं आध्यात्मवाद की शिक्षा आदि क्षेत्रों की शिक्षा के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान रहा है। यह आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा देश को विपरीत परिस्थितियों से उभारने में महत्वपूर्ण रही है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय बिट्रिश हुकुमत के विरोध में स्वराज एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का बालगंगाधर तिलक या महात्मां गाँधी आदि ने भारतीय जनता को अपने नेतृत्व के माध्यम से यह चैतना जागृत करने का प्रयास किया कि भारतीय मूल्य और संस्कृति आत्मनिर्भरता की रही हैं। जो वैदिक युग पर आधारित शिक्षा पद्धति का सार है।

हालाकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिस पर सदियों तक मुगल एवं बिट्रिश का शासन रहा। इन सभी ने अपनी–अपनी शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार–प्रसार किया, लेकिन कोई भी शिक्षा एवं संस्कृति भारत की परम्परागत व सनातन शिक्षा पद्धति के अस्तित्व को समाप्त नही कर सकी। क्योंकि भारत की शिक्षा एवं संस्कृति सत्यम शिवम सुन्दरम, वसुदैव कुटुम्भकम, बन्धुता आध्यात्मवाद एवं अहिंसा पर आधारित रही है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् उत्पन्न होने वाले परिवर्तनकारी आयामों का प्रभाव भारतीय शिक्षा के मूल्यों एवं आदर्शों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने लगा, जिसके लिए हम स्वंम भी जिम्मेदार है।

आध्यात्मवाद की शिक्षा हो, योग की शिक्षा हो, प्राकृतिक उपचार एवं आयुर्वेद की शिक्षा हो। इन सभी को विश्व के सभी देशों ने माना है, और यह भारत की विश्व को महत्वपूर्ण देन हैं। भारत की इन शिक्षा पद्धतियों से लाभान्वित होकर अमेरिका जैसे देश इन पर अपना ट्रेड़मार्क देने की बात करने लगे है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है हम जानते सब है लेकिन मानते नही है। हमारे सिद्धान्त अस्थिर एवं कथनी और करनी में अन्तर को दर्शाता है विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति को लेकर। एशिया के देश चीन और जापान ने अपनी शिक्षा एवं संस्कृति के आधार पर ही अपना विकास किया है। जबकि भारत की शिक्षा पद्धति व्यापारिक न होकर आत्मनिर्भरता पर आधारित रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिकतापूर्ण व व्यक्तित्व निर्माण केन्द्रित शिक्षा

ममता शर्मा

विभागाध्यक्ष –डी0एल0एड0 विभाग, बाबू कामता प्रसाद जैन महाविद्यालय, बडौत (उ0प्र0)

E-mail : mamta.bkpjm@gmail.com

'वृत्तं यत्नेन् रक्ष्येत् वित्तमेति च याति च ।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः ।।'

प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य के चरित्र तथा नैतिकता का महत्व वर्णित है। ''चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है, चला जाता है। धन से क्षीण व्यक्ति हीन नहीं है, बल्कि चरित्र से भ्रष्ट व्यक्ति हीन होता है।'' भारतीय संस्कृति इसी प्रकार की अवधारणा की पोषक रही है, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियॉ बदल चुकी है। भौतिकता की चकाचौंध, दिखावे की हावी होती प्रवृत्ति ने हमारे समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी है । शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के बावजूद आज का मानव संवेदना, नैतिकता तथा परस्पर सहयोग जैसे मूलभूत गुणों की अनदेखी कर बैठा है। परिणाम दंगे, फसाद, हिंसक प्रदर्शनों, युवा वर्ग के अपराधों में लिप्त होने के रूप में हमारे सामने है।

समाज में बढती अनैतिकता तथा अराजकता के कारणों पर यदि विचार किया जाए तो सबसे बडे कारण उभरकर आते हैं–भौतिकवादिता पर अत्यधिक बल शिक्षा का राजनीतिकरण, स्मार्टफोन का दुरूपयोग, उच्च शिक्षण संस्थानों में अराजकता की स्थिति, आध्यात्मिकता की उपेक्षा आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मनुष्य पशुतुल्य होता है, शिक्षा उसके व्यवहार को परिष्कृत कर उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास करती है , परंतु शिक्षित वर्ग का भी अपराधों में लिप्त होना आत्मकेन्द्रित व स्वार्थी होकर रह जाना तथा दिखावे पर ही बल देना चिन्तनीय स्थिति है। इस गम्भीर स्थिति से बाहर लाने का पुनीत कार्य यदि संभव है तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।

समाज के जिम्मेदार नागरिकों, विशेषकर अध्यापक वर्ग जिन पर भावी पीढीयों के व्यक्तित्व निर्माण का दायित्व है, उन्हे यह समझना होगा कि ऐसी शिक्षा के कोई मायने नही है जो बौद्धिक ज्ञान तो दे किन्तु व्यक्ति को संवेदनहीन एवं स्वार्थी बना दे। वर्तमान शिक्षा के बोझ तले मनुष्य की आत्मा खोती चली जा रही है। समस्या के समाधान पर विचार करें तो हमें अपनी संस्कृति के मूल स्वरूप् आध्यात्मिकता की ओर वापस लौटना होगा। प्रारम्भ से ही नैतिकता, देशभक्ति, सदाचरण का भाव बालकों के मन में विकसित कर हमें ''वसुधैव कुटुम्बकम'' का आदर्श छात्रों के सम्मुख रखना चाहिए।

शिक्षकों को दृढतापूर्वक इस बात पर बल देना चाहिए कि शिक्षित होकर भी यदि व्यक्ति में सामाजिक गुणों का अभाव है तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। व्यवहार में शालीनता तथा परस्पर सम्मान भाव के लिए सर्वोच्च आदर्श वाक्य जो शास्त्रों में कहा गया है–''आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत्।'' अर्थात स्वयं के लिए जो व्यवहार अनुचित लगे, उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए।'' इस सदवाक्य को हमें अपना आर्दश बनाना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प लेकर हम समाज में उच्च नैतिक आदर्शों वाले नागरिकों का निर्माण कर पायेंगे तथा शिक्षा के माध्यम से 'राष्ट्रीय चरित्र' विकसित कर पाने में निश्चय ही सफल होंगे।

भारतीय शिक्षा पद्धति का परिदृश्य : भूत से वर्तमान तक

डॉ. निमिश कुमार चौधरी

हाई स्कूल, पिन्दरुच, दरबंगा, बिहार

E-mail: namishchoudhary2@gmail.com

भारत युगों से दुनिया को ज्ञान की क्षेत्र में रास्ता दिखता आ रहा है। हजारों वर्षों से हमारे वेद–उपनिषद का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हमारे यहाँ सबसे प्राचीन नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जहां पूरी दुनिया से लोग शिक्षा लेने के लिए लोग आया करते थे। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, शंकराचार्य, कालिदास, विद्यापति, वारहमिहिर आदि जैसे विद्वानों ने अपने ज्ञान से भारत को विश्व में गौरवान्वित किया। ज्ञान के क्षेत्र में हमारी विरासत सबसे प्राचीन और निःसंदेह सबसे महान है। हमारी इस विरासत को बाहरी हमलावरो जैसे गौरी, बाबर आदि ने सबसे ज्यादा नुकशान पहुंचाया। बख्तियार खिलजी (तुर्की शासक) ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी थी और वहा इतनी पुस्तकें थी की पूरे तीन महीने तक पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेकों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। बाद में अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद के लिए शिक्षा को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आज़ादी के समय शिक्षा के लिए बस कुछ गुरुकुल (जैसी सामुदायिक व्यवस्थाएं), मिशनरी स्कूल और गिने–चुने निजी स्कूल थे। जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तब भारतीय शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी। साल 1951 में लगभग 13 हजार प्राथमिक और 7,000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। उस समय साक्षरता दर सिर्फ 12 प्रतिशत थी, जो आज 74 प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा बजट साल1951 में 1,144 मिलियन था तो वहीं 2017 के बजट में शिक्षा पर 79,685.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बहरहाल, शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के 7 दशकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो अभी भी जारी हैं। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की गई। साल 2009 में भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर और इंटरनेट क्रान्ति को बेहतर करने के लिए 'एडुसैट' (EduSat) उपग्रह साल 2004 को छोड़ा गया। अगर इसी तरह हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे तो आने वाले वर्षों में 100 फीसदी साक्षरता दर प्राप्त कर लेंगे। जो हमें पुनः विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

ग्रमीण क्षेत्र में शिक्षा की दशा

परमानन्द महतो

सहायक अध्यापक, पूर्णिया, बिहार

E-mail : pm93049711@gmail.com

शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यह व्यक्ति के समाजिक और मानसिक गुणों का विकास में अहम भूमिका निभाती है। सरकारी शिक्षण संस्थान का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की रौशनी पहुँचाना है। देश की आत्मा गाँवों में बसती है। किन्तु वहाँ शिक्षा की समुचित व्यवस्था नही है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की 70% जनसँख्या गाँवों में निवास करती है। यहाँ आज भी शिक्षा व्यवस्था सुधार की बाँट जोह रही है। गाँवों के विद्यालयों में आधारभूत संरचना का अभाव है। कई विद्यालय भूमिहीन एवं भवनहीन है। प्रर्याप्त शौचालयों का अभाव है। साथ ही छात्र– शिक्षक अनुपात असंगत है। कई विद्यालय सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अधिकांश विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नहीं है।

गाँवों में गरीबी के कारण बच्चों को अपने माता पिता के आर्थोपार्जन में सहयोग देना पड़ता है। इसके लिए वे कमाई करते हैं। कई बच्चे इस कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। माता–पिता घर में अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। विद्यालय में भी उन्हें समुचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। उनकी नींव कमजोर पड़ जाती है। वे पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के अभाव के कारण ग्रामीण विद्यालयों की दशा शोचनीय है। शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इसकी पहुँच से दूर है। विज्ञान मेला, प्रतियोगिताएँ, खेलकूद का आयोजन स्थल भी प्राय शहरी विद्यालय ही हुआ करते हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इन आयाजनों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि की भूमिका कम है। तकनीकी संस्थानों में इसकी नगण्य उपस्थिति है। उनमें जागरूकता की कमी संसाधनों की कमी एवं मार्गदर्शन का अभाव साफ–साफ देखा जा सकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय खुलचुके हैं। किन्तु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नही हो पा रही है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी शिक्षा संस्थानों में आमूल–चूल परिर्वतन की दरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में समुचित उत्थान के बिना विकसित भारत की कल्पना सरकार नहीं हो सकता।

कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग

विकास मलिक

सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, इदरीशपुर, विकास क्षेत्र–बिनौली, बागपत

E-mail : vikasmalik1999@gmail.com

कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार हर बच्चा भी अलग होता है, इसलिए वह एक विशिष्ट तरीके से सीखता भी है। विभिन्न शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि शिक्षार्थियों को अगर एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करके पढ़ाया जाए तो वे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। अधिगम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियां सुनना, देखना, सूंघना, चखना और छूना है। एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग हो तो यह भी जरूरी है कि बच्चे पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी ज्ञान अर्जित करें जो आज के आधुनिक समय में सर्वाधिक सुलभ अधिक से अधिक डिजिटल और बाह्य संसाधनों के रूप में हम सभी को उपलब्ध है। इसी पृष्टभूमि को ध्यान में रखते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) शिक्षण–अधिगम में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आईसीटी के प्रयोग से जहां शिक्षण बहुत सहज और सरल है वही शिक्षण में भी विषय–वस्तु के स्वरूप के आधार पर सही मीडिया/तकनीक का चयन करना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।आईसीटी को उपयोग करने के लिए विषय–वस्तु के स्वरूप को समझना ही नही वरन उपयुक्त ढंग से चयन करने के लिए शिक्षक को विषय–वस्तु के साथ–साथ विभिन्न आईसीटी माध्यमों का ज्ञान भी होना चाहिए।आईसीटी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने में तभी सक्षम होंगे जब शिक्षक विषय–वस्तु का विश्लेषण कर पाएँ उसके अनुरूप उपयुक्त मीडिया का चयन कर सकें और उसे उचित ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकें जिससे विद्यार्थी आसानी से विषय–वस्तु समझ सकें। आईसीटी उपकरण केवल तभी कारगर साबित होते हैं जब इसका उपयोग विषय–वस्तु और शिक्षण अधिगम के अनुरूप हो।आईसीटी द्वारा उन वस्तुओं ,जानकारियों आदि को आसानी से दिखाया जा सकता है, जिन्हें परम्परागत शिक्षण में आसानी से सुलभ नहीं कराया जा सकता था परन्तु यह शिक्षक पर ही निर्भर करता है कि वह शिक्षण अधिगम पद्धति पर आधारित उपयुक्त आईसीटी माध्यम का उपयोग करें। जहां आईसीटी सस्ता और सुलभ साधन है वहीं यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा एवं जानकर शिक्षक ही परिचय, व्याख्या, सारांश आदि जैसे उद्देश्यों पर आधारित आईसीटी माध्यमों का चयन कर सकता है। इस प्रकार साथ ही यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक पद्धति की अपनी–अपनी क्षमता है और उसी के अनुसार उसकी आईसीटी में भी अलग ज़रूरतें हैं। शिक्षक में किसी भी पद्धति का विश्लेषण करने की क्षमता और आईसीटी में उसकी विशेष ज़रूरतों की भी जानकारी होनी चाहिए। तभी वे उपययुक्त आईसीटी मीडिया माध्यम का चयन कर पाएँगे और शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे।

शिक्षक स्वायत्तता बनाम उत्तरदायित्व

पूरन लाल

सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बरुआ बेहड़, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश

E-mail: pooranlalchaudhry@gmail.com

शिक्षक समाज का पथप्रर्दशक होता है। यदि शिक्षक स्वायत्त हो और उसे अपने विवेकानुसार निर्णय लेने व कार्य करने की स्वायत्तता दी जाये तो वह समाज की दिशा ही बदल सकता है। परन्तु आज शिक्षक को अनेक नियमों और परम्पराओं में बॉधकर रखा गया है। शिक्षक की स्वायत्तता समाप्त हो गयी है, क्योंकि शिक्षक समयसीमा, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि जैसी अनेक जंजीरों में जकड़ा हुआ है जहॉ वह स्वयं चिन्तन, मनन और निर्णय लेने का अधिकार खो चुका है। शिक्षक विद्यालय में व अपनी कक्षा में समय देने की अपेक्षा उसका समय एमडीएम बनबाने में, उसकी निगरानी करने में, फल वितरण, दूध वितरण, पुस्तक वितरण, ड्रेस वितरण, जूता मोजा वितरण, बैग वितरण इन वितरणों का हिसाब बनाना सूचनायें तैयार करना, नित नये प्रपत्रों पर सूचना बनाना, उन सूचनाओं को अधिकारियों तक पहुॅचाना आदि इन्हीं कार्यो में व्यतीत हो जाता है। वह अपनी कक्षा में समय कम दे पाता है जिससे समाज में शिक्षक का सम्मान व गरिमा कम होना स्वाभाविक है। आजकल नई शिक्षण विधि और नवाचार के नाम पर शिक्षक को प्रशिक्षण में बहुत सारा समय बिताना पड़ता है। शिक्षण की एक विधि का प्रशिक्षण लेका वह अपनी कक्षा में पहुॅचता है, तब तक एक नई विधि का प्रशिक्षण लेने का आदेश आ जाता है। शिक्षक स्वयं में एक विद्वान होता है, वह परिस्थिति व बच्चे की मनोदशा के अनुसार स्वयं विधि खोज लेता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया तभी सुचारु चलती है जब शिक्षक स्वायत्त हो।

कभी कभी देखा गया है कि कुछ शिक्षक भी अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाते, उनका मन शिक्षण कार्यों में लगने की अपेक्षा राजनीति व व्यवसाय में अधिक लगता है, जिस कारण पूरे शिक्षक वर्ग का सम्मान खोता जा रहा है। शिक्षक को स्वयं यह उत्तरदायित्व लेना होगा कि जिस कारण विभाग ने उसे भर्ती किया है,जिस कार्य का उसे वेतन मिल रहा है, वह निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाहन करे। तभी शिक्षक समाज में अपना खोया सम्मान पा सकेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि शिक्षक ही समाज का पथप्रर्दशक होता है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग

डॉ. अनीता सिंह

लेक्चरर, श्रीनाथ बी.एड कॉलेज, आमथला, सिरोही, राजस्थान

E-mail : anitasinghbaghel89@gmail.com

प्रौद्योगिकी जीवन और समाज के हर पहलु को छु रही है। आजादी के बाद लगभग देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली काफी बड़े आकार में उभरी है जो देश भर में विभिन्न स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी का शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान में शिक्षा ही नहीं जीवन में भी प्रौद्योगिकी एक अहम् भूमिका निभा रही है। विद्यार्थी हो या शिक्षक दोनों के लिए प्रौद्योगिकी सभी कार्यों के लिए सहयोग करता है। शिक्षा में निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग करना शिक्षा में तकनीकी है। शिक्षा तकनीकी में श्रव्य–दृश्य सामग्री में अप्रेक्षित (पुस्तक मुद्रण सामग्री आदि) प्रेक्षपित (प्रोटेक्ट स्लाइड फिल्म) इलेक्ट्रॉनिक्स (कंप्यूटर, सीसीटीवी,ट्रांसमिशन) आदि मानव निर्मित प्रौद्योगिकी का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग हो रहा है।

वर्तमान में स्मार्ट क्लासेज का भारत में प्रचालन बढ़ रहा है जिसमें कंप्यूटर, वेबसाइट, माइक्रोफोन व स्पीकर, मोबाइल, स्मार्ट बोड्र्स एवं प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव

डॉ0 दिलीप कुमार मौर्य

असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग,

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय फाफामऊ, प्रयागराज , उत्तर प्रदेश

E-mail : dkmdefence@gmail.com

प्रौद्योगिकी भगवान का एक उपहार है। जीवन के उपहार के बाद यह शायद भगवान के उपहारों में सबसे बड़ा है। यह कलाओं और विज्ञानों की सभ्यताओं की जननी है। प्रौद्योगिकी ने निश्चित रूप से हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। इसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किय है और जीवन को पुर्न परिभाषित किया है। निःसंदेह प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई मैनुअल कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद। साथ ही, आधुनिक तकनीक की मदद से कई जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को आसानी और अधिक दक्षता के साथ किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। स्कूलों में प्रौद्योगिकी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, शिक्षा में कम्प्यूटर की शुरूआत के साथ, शिक्षकों के लिए ज्ञान प्रदान करना और छात्रों के लिए इसे प्राप्त करना आसान हो गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग ने शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सुखद बना दिया है।

भारत में कृषि शिक्षा और अर्थव्यवस्था में संबंध

डॉ आशीष कुमार

विषय विशेषज्ञ, उद्यान विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

E-mail: dr.ashishkumardangi@gmail.com

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 67% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि क्षेत्र खाद सुरक्षा रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक व सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों लोगों का कृषि के प्रति मोहभंग होना एक चिंता का विषय है। आधुनिक कृषि ज्ञान आधारित है अतः इसमें सभी स्तरों की शिक्षा का विशेषकर उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का महत्व और विभिन्न पड़ाव की व्याख्या अति आवश्यक हो गई है। भारत में चल रही कृषि शिक्षा अमेरिका की लैंड ग्रांट व्यवस्था पर आधारित कृषि विश्वविद्यालय बने गौरतलब है कि अमेरिका में इस प्रकार के शुद्ध कृषि विश्वविद्यालय नहीं है इसी का परिणाम है कि कृषि विश्वविद्यालय सामान्य विश्वविद्यालयों जैसे विज्ञान कला वाणिज्य एवं मानव शास्त्र आदि से अलग–थलग हो गए है।

आज के कृषि महाविद्यालयों का ढांचा कामकाज और उद्देश्य किसी भी प्रकार से राधा कृष्ण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के ग्रामीण विश्वविद्यालयों के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है। परिणाम स्वरूप इन कृषि महाविद्यालयों का ग्रामीण विकास में जो योगदान होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। हरित क्रांति के आरंभ में बीजों की किस्मों में विविधता पर बहुत ध्यान दिया गया जिससे अनाज के उत्पादन में वृद्धि तो हुई किंतु उपयुक्त ज्ञान के अभाव में यह कृषि के स्थायित्व सजीवता हटाने का कारण भी बनी क्योंकि कृषि भारत का एक अहम क्षेत्र है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए कृषि महाविद्यालयों की कृषि से दूरी को खत्म करने और विविध विषयों वाले विश्वविद्यालयों से आपसी तालमेल बढ़ाने का समय आ गया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहान से होकर गुजरता है।

वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा एवं विदेशी उच्च शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

देवराज सिंह

शोधार्थी, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा एवं विदेशी उच्च शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इक्कीसवीं सदी में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति हुई है। लेकिन अभी भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्वस्तरीय गुणवत्ता नहीं प्रदर्शित कर पाई है। भारत में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र मौजूद है। भारतीय विश्वविद्यालय हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एवं कैंब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से अभी भी बहुत पीछे है। इस शोध पत्र का उद्धेश्य भारतीय उच्च शिक्षा में उपस्थित उन सभी बिन्दुओं की पहचान करना, जिनके कारण हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था कमजोर बनी हुई है और साथ ही साथ उन सभी कमियों का व्यवहरात्मक निराकरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में नयी शिक्षा नीति जारी की गयी है। इस नीति के उच्च शिक्षा पर दूरगामी परिणामों का आंकलन भी इस शोध पत्र में किया गया है। इस शोध पत्र में सरकारी विश्वविद्यालयों पर विशेष कार्य किया गया है। वर्तमान में हम चतुर्थ औद्योगिक क्रान्ति में प्रवेश कर चुके है, लेकिन हमारे उच्च शिक्षा का स्तर अभी भी ब्रिटिश काल में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर बना हुआ है। भारत में पूंजी की प्रचुरता के बावजूद भी उच्च शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तन बहुत कम हुए हैं और तकनीकी स्तर पर भी भारत के आईआईटी जैसे संस्थान एमआईटी से बहुत पीछे हैं। विश्व स्तरीय शोध जर्नलों एवं पत्रिकाओं में भी भारतीय शोध कर्ताओं की भागीदारी बहुत कम ही रहती है। हम कैसे इस भागीदारी को बढ़ा सकते है? और भारतीय उच्च शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, इस शोध पत्र में यह दर्शाया गया है।

शिक्षा का व्यापारीकरण : शिक्षा गुणवत्ता का पतन?

अमित कुमार

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

E-mail: kabir199097@gmail.com

शिक्षा के व्यापारीकरण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की ओर अग्रसर है। ज्ञातव्य है कि राज्य सहायता प्राप्त शिक्षा प्रणाली निम्न गुणवत्ता पर स्थिर हो चुकी है तथा पिछले कई वर्षों में भी सरकारी शिक्षा प्रणाली में अनेकों खामियां हैं जैसे निम्न अवसंरचना शोध प्रकृति सृजनशीलता की कमी इत्यादि। वहीं निजी क्षेत्र में शोध प्रवृत्ति उचित संरचना इत्यादि के कारण अभ्यर्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो रहा है। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों द्वारा शोध व पाठ्यक्रम पर अधिक व्यय किया जा रहा है जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा एक प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था को जन्म दे रहा है। यद्यपि निजी क्षेत्र की अच्छी गुणवत्ता का स्वरूप वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर महिला शिक्षा को भी निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि एक सराहनीय प्रयास है। व्यवसायिक वा पेशेवर पाठ्यक्रम वर्तमान में युवाओं को बेहतर विकल्प प्रदान कर रहे हैं तथा निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा इन पाठ्यक्रमों को बाजार की मांग के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है। जिससे नौकरी या व्यवसाय मैं युवाओं को उचित विकल्प प्राप्त हो सके।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिकतापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण व व्यक्तित्व–निर्माण केन्द्रित शिक्षा

डॉ0 किरन गर्ग

असि0 प्रोफेसर, बी0 एड0 विभाग, दिगम्बर जैन कॉलिज, बड़ौत, बागपत, उ0 प्र0

दिमाग की दहलीज पर दस्तक मशीन की ये झंकार है आधुनिकता दस में से आठ शहरी महिलाएँ, इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं। दुनियाभर में आज अरबों लोग मोबाइल डिवाइस से जुड़े हैं। कृत्रिम बुद्विमता, जो भावनाओं, विचारों को समझे और जिस काम को करने में आपको महीने लगते हो, उसे चंद मिनटों में ही पूरा करके दे दे, तो लगता है कि हाँ, दुनिया तरक्की कर रही है। हम बदल रहे हैं। लेकिन किसी भी देश की प्रगति जनसाधारण की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है जिसमें नैतिकता, गुणवत्ता समाहित है। इक्कीसवीं सदी की शिक्षा के मूलतः चार स्तम्भ है जिनमें पहला– स्तम्भ सीखने की कला, दूसरा– कार्यों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करना, तीसरा– अपनी क्षमताओं को पहचानना और चौथा– एक–दूसरे के साथ सौहार्द के साथ रहना। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति यहाँ की शिक्षा पद्वति पर निर्भर करती है। वर्तमान में कला, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि अनेक संकायों में विभिन्न संवर्गों में शिक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक प्रचार हो रहा है। सूचना प्रौधोगिकी के क्षेत्र में या कम्प्यूटर शिक्षा से भारत विश्व का अग्रणी देश बन गया है, फिर भी एक कमी यह है कि यहाँ नैतिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप भारतीय पीढ़ी सांस्कृतिक एवं कोरी भौतिकतावादी बन रही है। जबकि विद्यार्थी जीवन आचरण की पाठशाला है। हाँ वह अपने व्यक्तित्व एवं सुंदर चरित्र का निर्माण कर सकता है और देश में उच्च आदर्शो, श्रेष्ठ परम्पराओं एवं नैतिक मूल्यों की भी स्थापना कर सकता है। ऐसे में छात्रों के लिए नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा देना, मूल्यांकन करना, आचरण एवं व्यावहारिक रूप में अमल करना, वर्तमान की आवश्यकता है। शिक्षा एक बीज है और जीवन वृक्ष है जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर नम्रता, ईमानदारी, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और शांति गुणरूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधुरी है।

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सरकारी शिक्षा में चुनौतियाँ एवं समाधान

सरिता

एम0एड0 छात्रा, बाबू कामता प्रसाद जैन महाविद्यालय, बडौत (बागपत), उत्तर प्रदेश

Email : saritachaudary.bkpjm@gmail.com

'सां विद्याां या शास्ति,
स विद्या या विमुक्ताये।

अर्थात जो हमें अनुशासित करती हैं वह विद्याा है, जो हमें मुक्ति देती है वह विद्याा है।

शिक्षा उस संजीवनी की भॉति है जो अज्ञानरूपी मरूस्थल में भी ज्ञान की गंगा बहाती है। शिक्षा व्यक्ति समाज और राष्ट्र प्रगति के लिये आवश्यक है। शिक्षा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करती है। इस बात का समर्थन विद्धानो द्वारा समय–समय पर धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। गुरू ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है– विद्याा विचारी तां परोपकारी। कुरान शरीफ का पहला वाक्य है– 'इकरा'' अर्थात पढो।

हमारे देश में सामान्यतः शिक्षा के तीन स्तर है– प्राथमिक, माध्यामिक एवं उच्च शिक्षा। यदि हम चुनौतियों की बात करते है तो हमारे समक्ष तीनो ही स्तर पर बहुत सारी चुनौतियॉ आती है। मुख्यतया प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर मध्यवर्ग का एक बडा हिस्सा अपने बच्चो को अंग्रजी शिक्षा दिलाने के पक्ष में है। अतः वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलो से निकालकर प्राइवेट स्कूलो में प्रवेश दिलाते है। इसी वजह से सरकारी स्कूल गरीबों और आशिक्षितों के बच्चों का सहारा बन गए है। जहॉ इन्हे नौकरशाही और शिक्षक संघों की दया पर रहना पडता है। इसके परिणाम स्वरूप इन स्कूलो के पाठ्य–पुस्तकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता, विद्यार्थीयों की उपलब्धियो के निरीक्षण का विकास थम गया है।

माध्यमिक शिक्षा का जिक्र आते ही बोर्ड परीक्षाओं का जिक्र आता है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा कॉलेज की तैयारी का इंट्री प्वाइंट होती है। माध्यमिक स्तर पर अनेक चुनौतियॉ प्रस्तुत होती है जैसे – अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला की खराब सिथति, छात्र–शिक्षक का अनुचित अनुपात, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, आदि।

इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी अनेक समस्याएँ हमारे सामने आती है जिसमें सबसे अहम है छात्रों का महाविद्यालय न आना।

इन सभी तीनों स्तर पर सुधार हेतु हमें अनेक उपाय करने होगें। प्राथमिक स्तर पर हमें शिक्षण विधियों में बदलाव कर काफी हद तक समस्याएँ हल कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर हमें गतिविधियाँ आधारित शिक्षण करना होगा। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में बदलाव की सबसे अधिक आवश्यता है। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दी जा रही है वह कॉलेज के लिये कितनी उपयोगी है? माध्यामिक व उच्च स्तर पर छात्रो को सार्थक गतिविधियों से जोडा जाए। छात्रो में टीम भावना संचार और और नेतृत्व के गुणों उद्यमिता के भाव और महत्वपूर्ण निर्णयन क्षमता का समावेश हो।

प्राथमिक माध्यमिक व उच्च सरकारी शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि करने में सबसे अहम भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षकों को चाहिये कि वे शिक्षण कार्य को पूर्ण निष्ठा भाव से तथा शिक्षण को अपना कर्त्व्य समझे न की मात्र व्यवसाय या नौकरी।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढंडेरा, विकासखंड नारसन, हरिद्वार (उत्तराखंड) में "प्रगति" पुस्तकालय की स्थापना

अरविंद कुमार (राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त)
(प्रभारी) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, विकासखंड ढंडेरा, हरिद्वार ,उत्तराखंड
E-mail : kumararvind 60759@ gmail.com

"प्रगति" पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रदेश में 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो जाता है। जब सत्र 2019–20 में प्रवेश हो रहे थे, वहीं धीरे–धीरे एक नई समस्या भी जन्म ले रही थी और वह समस्या थी बच्चों के दाखिले के बाद पुस्तकों की; क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका था एवं सरकार द्वारा प्रदेश में बच्चों को पुस्तक न देखकर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग छह–सात महीने का समय लगता है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा एक बैठक में विचार किया गया कि क्यों न हम सभी अध्यापकों द्वारा अपने–अपने विषय की पुस्तकें खरीद कर विद्यालय रख ली जाए और उनसे ही अपना शिक्षण कार्य एवं अन्य कार्य किए जाए।

इसी के चलते मेरे मन में विचार आया क्यों न हम अपने विद्यालय में शून्य निवेश करके एक लाइब्रेरी ही बनाए। लेकिन इस सब प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि शून्य निवेश करके विद्यालय में लाइब्रेरी कैसे बनेगी? फिर भी चुनौती को स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया एवं जनसंपर्क के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुझे मेरे शिक्षक साथियों एवं मित्र समुदाय का सहयोग मिलना प्रारंभ हुआ और मेरे हौसले को मानो चार चाँद लग गए हो। परिणामस्वरूप, आज हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में 122 पुस्तकें मौजूद हैं, जिनमें मुख्यतः महापुरुषों पर आधारित, प्रेरक प्रसंग, एनसीईआरटी बुक्स, स्वतंत्रता सेनानी, प्रतियोगिताओं से संबंधित, क्विज संबंधित, भारत का संविधान, अंबेडकर जीवनी आदि।

"प्रगति" पुस्तकालय का उद्देश्य :

- सिलेबस संबंधी समस्या का समाधान।
- देश प्रेम की भावना का विकास करना।
- शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
- समूह में कार्य करने की भावना का विकास।
- अतिरिक्त ज्ञान वृद्धि समय का सदुपयोग आदि।
- प्रतियोगिताओं की तैयारी।
- महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा पाकर खुद को देशभक्ति से जोड़ना आदि।

वर्तमान में आज मेरे विद्यालय का "प्रगति" पुस्तकालय नेशनल अवॉर्डी बन चुका है। विगत 27 फरवरी 2020 से 3 मार्च 2020 तक आईआईटी दिल्ली में नवाचार कार्यक्रम के अंतर्गत एमएचआरडी मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

स्रोत : शिक्षक साथी, मित्र ,समुदाय; **लाभार्थी :** प्यारे बच्चे एवं शिक्षक।

"तक्षशिला विश्वविद्यालय" चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण के सन्दर्भ में

अन्जू लता श्रीवास्तव

शोध छात्रा, गुरुकुल कागंडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, उत्तराखंड

E-mail: anjulata20@gmail.com

प्रत्येक देश की संस्कृति व सभ्यता के विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य अंग है क्योकि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव की उन अंतर्निहित शक्तियों कुशलताओं एवं गुणों का विकास होता है जिनसे वह अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। प्रारम्भ से ही शिक्षा का समाज के भौतिक आध्यात्मिक सर्वांगीण सुख समद्धि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा सभ्य समाज का प्रतिबिम्ब हैं। भारतीय शिक्षा प्रारम्भ में धर्म प्रधान थी। समाज की आवश्क्तानुसार शिक्षा के स्वरूप में विकास हुआ। मनुष्य की विभिन्न विषयो में अभिरूचि व ज्ञान पिपासा के लिए विभिन्न शिक्षा केन्द्रो की स्थापना हुई। छठवी शताब्दी में उदित बौद्ध धर्म एक तार्किक और बुद्धिवादी विचारधारा का द्योतक था। शिक्षा को सार्वजनिक बनाने तथा शिक्षण संस्थाओं को समृद्ध रूप देने में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भिक्षुओं एवं जन सामान्य के कल्याण के लिए बौद्ध विहार महत्वपूर्ण शिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित हुये। जहॉ पर शिक्षा का प्रबन्ध बौद्ध उपासको के साथ ही जन सामान्य के लिए भी किया गया। इस समय राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु आदि नगरी में कई प्रसिद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जो कालान्तर में शिक्षण के प्रमुख केन्द्र बन गये। तक्षशिला, नालंदा, वाराणसी आदि उच्च शिक्षण केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध थे। तक्षशिला चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। शिक्षण संस्थानों को आधुनिक रूप देने में बौद्ध धर्म का विशिष्ट स्थान परिलक्षित होता है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्राचीन भारत में शिक्षण केन्द्र के अर्न्तगत तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण प्रशिक्षण का साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यो के आधार पर विवेचन किया जाएगा।

शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह

प्राचार्य, दिगम्बर जैन कॉलिज, बड़ौत, बागपत, ;उ0 प्र0

कसी समुदाय का संगठन उसके सदस्यों के जीवन–यापन और शिक्षा–दीक्षा की व्यवस्था हेतु 'हम की भावना' पर आधारित है। समुदाय मनुष्य का व्यक्तित्व एवं उसकी क्रियाओं का विकास पूर्णरूप से करता है। जैसा समुदाय होता है वैसी ही शिक्षा प्रणाली होती है। आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास करना है और उन्हें किसी उद्योग या उत्पादन कार्य में लोकतन्त्र में सुहा, योग्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाना है। सोशल मीडिया का चहुंओ दुष्प्रभाव तथा मूल्यों का संरक्षण एवं विकास हेतु आज धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। परिवार व विद्यालय के समुदाय हमें इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। बालक के व्यक्तित्व पर समुदाय का गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक की संस्कृति, आचरण, रहन–सहन, बोलचाल, विचार, स्वभाव, आदतें आदि के निर्माण में भी समुदाय का परोक्ष, प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः देखने में आता है कि कलाकार के साथ रहने वाला बालक उसकी कला से प्रभावित हो जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थान, राजनीतिक दल, विद्यालय, समाज–सेवा, यात्रायें, घर, पास–पड़ोस, क्रीड़ा स्थल आदि सामुदायिक इकाईयां भी बालको की शिक्षा और उसकी सर्वागीण विकास में भूमिका निभाते हैं। जैसेकि–विद्यालय समुदाय द्वारा सामुदायिक सेवा कार्यों का आयोजन किया जाता है। विद्यालय सामुदायिक हित के लिए सार्वजनिक सफाई, वृक्षारोपण, प्रौड़शिक्षा, नारी सुरक्षा आदि योजनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। विद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना – ;एन. एस. एसद्ध ;एन.सी. सीद्ध ;स्काउटिंगद्ध आदि को शिविर के माध्यम से भी समाज की सेवा करने का प्रयास किया जा सकता है। यदि हम समाज सेवा करेगें तो हम काफी हद तक समाज में फैली कुरीतियों, अन्धविश्वासों, गरीबी को दूर कर सकते हैं। 'सेवा परमो धर्मः को' आत्मसात करने वाला ही भविष्य में महामानव की उपाधि प्राप्त करता है। निष्पक्षता और निस्वार्थ भाव से किया गया हर प्रयास नये भारत की नींव है। अर्थात् मानवता की सेवा सर्वोच्च धर्म है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग

कु. शाईस्ता बेगम

रिसर्च स्कोलर, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ

शिक्षा प्रक्रिया और उसके परिणामों के सभी तरह के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबंधन में आज तकनीकी अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। ऐसा सब कुछ करने में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान और सिद्धांतों ने ही अपना चमत्कार दिखाया है। तकनीकी ज्ञान एवं कौशल का यही व्यवहारिक पहलू शिक्षा जगत में शिक्षा प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा तकनीकी के प्रयोग से शिक्षक अच्छी तरह शिक्षण कर सकते हैं और विद्यार्थी अच्छी तरह अधिगम। शिक्षा का माध्यम अब बदलता जा रहा है। शुरुआत में, कोई किताब या कॉपी नहीं हुआ करती थी, शिक्षक कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाते थे छात्र वही सीखा करते थे। जैसे–जैसे वक्त बीतता गया कागज और कलम का आविष्कार हुआ और धीरे–धीरे यह प्रक्रिया बढ़ती गई और आज प्रौद्योगिकी हर जगह ही मौजूद है। प्रौद्योगिकी एक डिजिटल मंच प्रदान करती है और आजकल यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जहां कहीं भी हम जाते हैं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल,कॉलेज स्मार्ट कक्षाओं के नए टैग के साथ चल रहे हैं और ये स्मार्ट कक्षाएं प्रौद्योगिकी का सबसे बेहतर उदाहरण है। तकनीकी के उपयोग ने शिक्षा को आसान बनाने के साथ–साथ रोचक भी बना दिया है। आमतौर पर, बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब से यह स्मार्ट क्लासेस शुरु हुई है उसके बाद वह बस वही रहना पसंद करते हैं। इन स्मार्ट कक्षाओं के अलावा, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। वह सॉफ्टवेयर हमें अपडेट रखते हैं और नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। यद्यपि अभी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, और हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। यूट्यूब पर विभिन्न विषय उपलब्ध है और कई शैक्षिक ऐप उपलब्ध है। हम उनसे पढ़ सकते हैं और प्रतिदिन कई चीजें सीख सकते हैं। इस दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे देश के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अपने अध्यापकीय उत्तरदायित्व के भली–भांति निर्वहन के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समुचित ज्ञान हो। यह तभी संभव है जब कि अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान कौशल एवं उसके उपयोग के प्रति यथेष्ट अभिवृत्ति के विकास के लिए अपेक्षित अवसरों की उपलब्धि सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण अवसरों के माध्यम से भलीभांति सुलभ कराई जाए।

मुख्य शब्दः क्रियान्वयन, प्रबंधन, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी, डिजिटल मंच, स्मार्ट कक्षाएं, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, उत्तरदायित्व, यथेष्ट अभिवृत्ति आदि।

शांति शिक्षा का सैद्धांतिक परिदृश्य

प्रवेश कुमार

शोधार्थी, शिक्षक शिक्षा विभाग, डी0जे0 (पी0जी0), जैन कॉलेज, बडौत, बागपत

डॉ0 कविता अग्रवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, डी0जे0 (पी0जी0), जैन कॉलेज, बडौत, बागपत

भारतीय दर्शन में शान्ति शिक्षा कोई नयी बात नही यह हमारी शिक्षा व्यवस्था में अतिप्राचीन काल से प्रचलित रही है। विश्व के सभी धर्म और दर्शन मनुष्य को आन्नद की ओर उन्मुख करने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का सृजन करने के लिए शान्ति शिक्षा प्रदान करने की बात करते है। भारतीय दर्शन हमेशा से ही विश्वबन्धुत्व, मानव में पारसपरिक प्रेम और शान्ति पूर्वक जीने पर बल देता है। गौतम बुद्ध जी का जीवन तो इसका जीता–जागता उदाहरण है। इसी प्रकार महावीर स्वामी जी ने भी अहिंसा को परम धर्म बताया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मौहम्द ने भी विश्व के लोगों को समान्ता, बन्धुत्व और शान्ति पूर्वक रहने की शिक्षा दी।

पाश्चात्य जगत में भी पेस्टालॉजी, प्रोबेल आदि दार्शनिकों एवं शिक्षशास्त्रियों ने शान्ति शिक्षा का पूर्ण सर्मथन किया। भारतीय चिन्तकों – टैगोर, विवेकान्नद और गांधी जी ने भी शिक्षा औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शान्ति शिक्षा प्रदान किये जाने पर बल दिया।

किन्तु आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे समाज में जीवन यापन कर रहा है। जहां पर अधिकांश व्यक्तियों में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा एवं नकारात्मकता जैसे भाव व्यक्तियों के सामान्य विचारों में देखने को मिलते हैं। आज के समाज में मानवता, भाईचारा एवं प्रेम जैसे भावों का अभाव लोगों में देखने को मिलता है। जिसके घातक प्रभाव समाज की भावी पीढ़ी को चुकाने पड़ रहे हैं। सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि इसका मुख्य कारण नकारात्मक विचार, मानव का मानव के प्रति अविश्वास, सामाजिक मूल्यों की जानकारी का अभाव है। अतः इन्हीं सब कारणों को देखते हुए वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर शांति शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि विषय विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं के द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रमों में शांति शिक्षा के महत्व को स्थान प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत आलेख में शान्ति शिक्षा के अर्थ एवं उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। शान्ति शिक्षा समाज एवं मानव विकास के लिए विद्यालयी पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही शान्ति शिक्षा के उद्देश्यों एवं उसके कार्यान्वयन की रणनीति बनाने में विद्यालयों की मुख्य भूमिका बतायी गयी है।

नौकरी करने वाली एवं नौकरी नहीं करने वाली विवाहित महिलाओं की जीवन–संतुष्टि के आयामों का अध्ययन

डॉ. पार्वती यादव

असिस्टेण्ट प्रोफेसर (शिक्षा–विभाग), डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

अनुराधा उपाध्याय

पीएच. डी. शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश – महिलाओं का जीवन संघर्षो और परिवर्तनों से भरा रहता हैं जिनका उनके जीवन–संतुष्टि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः महिलाओं के जीवन–संतुष्टि एक महत्वपूर्ण विषय है। महिलाओं के प्रतिदिन की दिनचर्या जीवन–संतुष्टि का स्तर ऐसे तथ्य हैं जो अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में बिलासपुर शहर के शासकीय तथा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को चुना गया। जिनमें से 150 नौकरी करने वाली तथा 150 नौकरी नहीं करने वाली माहिलाओं को लिया गया। प्रस्तुत शोध में शोध उपकरण डॉ. प्रमोद कुमार और डॉ. जयश्री ध्यानी द्वारा निर्मित जीवन–संतुष्टि स्केल उपकरण का प्रयोग किया गया। हमारी परिकल्पना अस्वीकृत हुई है। अतः नौकरी करने वाली एवं नौकरी नहीं करने वाली विवाहित महिलाओं की जीवन–सन्तुष्टि अंतर पाया गया।

शब्द कुंजी – नौकरी करने वाली महिलाएँ, नौकरी नहीं करने वाली विवाहित महिलाएँ एवं जीवन–सन्तुष्टि इत्यादि।

शाहजहाँपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन पर, एक अध्ययन

सुदीप कुमार

शोध छात्र, शिक्षा संकाय सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी झुंझुनू, राजस्थान

प्रस्तुत शोध प्रपत्र एक शिक्षक के प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में चयनित होने के पश्चात् उसकी समायोजन की स्थिति को प्रकट करता है यह दर्शाता है कि किस प्रकार शिक्षा एक शिक्षक का महत्वपूर्ण अवयव हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के कार्य क्षेत्र में समायोजन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार से आंकड़ों को एकत्रित किया है। जो इस शोध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध रखते है। सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण करने के पश्चात केवल यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग है। जो एक व्यक्ति को सर्वोचच ऊंचाई पर भी ले जा सकती है एवं उसके अभाव में मनुष्य निम्न स्तर पर भी रह सकता हैं शिक्षक का समायोजन एवं कुसमायोजन बहुत कुछ उसके शिक्षा का निर्भर करता है।

मूलशब्दः– समायोजन, प्राथमिक, शिक्षक, शिक्षा, कुसमायोजन।

सरकारी शैक्षिक संस्थान : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां

डॉ0 आजाद प्रताप सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, एम0एल0के0पी0जी0 कॉलेज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश

Email:- pratapazad.singh@gmail.com

देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक–आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों से आता है, जबकि इन राज्य विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। UGC के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही मिलता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को स्कूल–पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में बाँटा है ताकि इसकी निरंतरता लगातार बनी रह सके। योजना का उद्देश्य अंग्रेजी के ज से बने शब्ददृ टीचर्स और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बाँटे बिना स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति के परिणामों पर आधारित है। योजना में सभी हितधारकों– माता–पिताध्अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, समुदाय तथा राज्यकर्मी आदि की सक्रिय भागीदारी होती है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। सरकारें भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिये निरंतर प्रयास करती रहती हैं। लेकिन इसमें भी राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के असफल हो जाने का जोखिम रहता है, क्योंकि वे परिवर्तन करते समय रोडमैप का अनुसरण नहीं करते और नीतियाँ बनाते समय सभी हितधारकों को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। टॉप–200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है। उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों से आता है, जबकि इन राज्य विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। न्ळब् के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही मिलता है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों के विपरीत है, जहाँ फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

योगाभ्यास में निहित औषधीय गुणः पातञ्जल योग के संबंध में अध्ययन

आदित्य कुमार

शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

E-Mail : adit092sh@gmail.com

स्वस्थ शरीर कि कामना करना हर मनुष्य की इच्छा रहती है। कहते है स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है। वर्तमान में शरीर के प्रति लोगों का रूक्षान आत्म योग द्वारा देखा जा सकता है। आत्म योग, योग का ही एक प्ररूप है, जिसके तहत योग के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया जाता है। जिससे सूर्य नमस्कार से लेकर प्राणायाम् तक के विभिन्न उपलब्धि को योग द्वारा समझा जा सकता है। योग द्वारा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ को भी ये दुरूस्त करती है। योग द्वारा हम शारीरिक उपचार ही नहीं बल्कि चेतना, शक्ति एवं स्फुर्ति भी विषय का भारत ही नहीं बल्कि पुरा विश्व इससे लाभांवित हो रहा है। इसके साथ ही योग में औषधि कि विभिन्न प्रकार मिल सकते है, जिसे विशेषकर पातञ्जल योग द्वारा संचलित योग पिठ को ले सकते है। इसके द्वारा आज व्यक्तियों के दुषित खाद्य एवं पर्यावरण में प्रदुषण का प्रभाव शरीर पर कम किया जा सकता है। जैसे प्राणायाम् फेफड़ों को स्वस्थ करना और अनुलोम–विलोम् द्वारा गैस, अनपच, एवं आंत से संबंधित बिमारियों को दुर किया जा सकता है। वहीं औषधी के रूप में जड़ी–बुटी, वाटिका एवं अन्य औषधी उपलब्ध है। जिसके द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है।

अतः संबंधित अध्ययन योगाभ्यास में निहित औषधीय गुणः पातञ्जल योग के संबंध में अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन बिहार के पटना, गया, एवं नवादा जिला के योग सिविर में 60 योगाभ्यास (उतरदाताओं) से प्रश्नावली के माध्यम् से योग के पूर्व एवं योग उपरान्त शरीर के रोग एवं उपचार से संबंध में पुछ कर पता लगाया। प्राप्त परिणाम योग से पूर्व में कुल 60 उत्तरदाताओं में 41 रोग्रस्त थे। जबकि 19 उत्तरदाताओं अभी भी कुछ औषधी एवं योग उपचार कर रहे है।

मूल्य शब्द :– योग, उपचार, पातञ्जल योग, औषधीय, एवं स्वास्थ्य।

बिहार माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका

ज्योति कूमारी

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, म0, वि0, वि0, बोधगया

E-mail : sweetjyoti2793@gmail.com

प्रस्ताविक अध्ययन ''बिहार माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रषासन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका'' का एक अध्ययन है। आज शिक्षा का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यापक एवं व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता होती है, ताकि शिक्षा के प्रशासन में सुशासन के गुण स्थापित कि जा सकें। भारत में प्राचीन काल से ही सुशासन की धारणा आध्यात्मिकता के आधार पर रही थी। वर्तमान में सरकार और शासन पर काफी चर्चाएं हो रही है। यद्यपि इन्हें एक दूसरे का पर्याय समझा जाता है। किन्तु सच्चे अर्थ में ऐसा इसलिए नहीं होता कि शासन, सरकार शब्द से व्यापक अर्थों में है। सरकार–तंत्र एवं संस्थागत व्यवस्थाओं के द्वारा सम्पादित सम्प्रभु शक्तियाँ, जिसका प्रयोग आंतरिक एवं बाह्य रूप से राजनीतिक समूह के हित में किया जाता है, जबकि शासन का अर्थ समाज की भलाई के लिए लिया गया आधारिक निर्णय, जिसमें प्रक्रिया एवं परिणाम संबंधित होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था निर्णय लेने की प्रक्रिया को इंगित करता है और इन प्रक्रियाओं का भी वर्णन करता है कि इसे कैसे लागू किया जाय? या नहीं किया जाएं। प्रशासनिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा स्थानीय स्तर पर भी लागू है।

शैक्षिक प्रशासन की सामाजिक एवं आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत नेतृत्व व्यवहार प्रशासनिक व्यवहार और निर्णय लेना इसकी मुख्य आधारशिला है। जिसके द्वारा सुशासन के सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। वहीं अगर बिहार में सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षिक प्रशासन में सुशासन व्यवस्था की बात की जाए तो, हम पाते हैं कि निम्न उत्पादकता एवं कार्यत कर्मचारी असंतोष एवं संघर्ष सूचना विस्फोट अथवा नवीन वातावरणीय चुनौतियां में प्रशासकों को चिंता में रखती है कि वह किस प्रकार शैक्षणिक व्यवस्था ने नेतृत्व व्यवहार प्रशासनिक व्यवहार तथा निर्णय शक्ति इत्यादि को किस प्रकार सुनिश्चित करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा से जुड़े अन्य समग्र एक चिंतनीय विषय है। जहां पर सुशासन व्यवस्था पूर्णता लक्ष्य पर आधारित होती है। वही कई ऐसी नीतियां भी सामने प्रकट आती है कि, इसकी संचालन किस प्रकार की जाए।

स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था में स्वामी विवेकानन्द की मानव निर्माण शिक्षा की उपादेयता

सुमित कुमार (शोधार्थी)

स्कूल ऑफ एजूकेशन, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड, (उ0प्र0)

Email – sumitkumarnzl@gmail.com

किसी भी देश की प्रगति और विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन वहॉ की शिक्षा है। एक उत्तम शैक्षिक पद्धति के द्वारा ही कोई राष्ट्र एवं समाज प्रगति के शिखर पर पहुच सकता है। स्वदेशी शिक्षा प्रणाली लम्बे समय से दुर्गमता और निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा का सामना कर रही है। जिससे भारतीय समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी, हत्या, बलात्कार, भाई-भतीजा वाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, लैंगिक असमानता, आदि अपने चरम पर हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली नवयुवकों को न तो रोजगार ही उपलब्ध करा पा रही है और न ही आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित कर पा रही है। चारित्रिक एवं नैतिक जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का ह्रास भी वर्तमान समाज की एक महत्पूर्ण समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है। ऐसे समय में भारत के विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री स्वामी विवेकानन्द जी के मानव निर्माण से सम्बन्धित उनके शैक्षिक विचार आज भी प्रासांगिक दिखाई पडते हैं। स्वामी विवेकानन्द जी ने वेदान्त सिद्धान्त एवं व्यवहारिक वेदान्त को लोकजीवन का सम्बल बनाया। वह शिक्षा को एक अचूक हथियार बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव हैं - "शिक्षा व्यक्ति में विद्यमान अर्न्तनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति हैं।" उन्होने किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक एवं आत्मिक ज्ञान के विकास पर भी बल दिया है। एक विद्यार्थी को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए ? यह प्रश्न एक और गम्भीर प्रश्न से सम्बन्धित है और वह यह है कि वह कौन से उद्देश्य हैं जो शिक्षा द्वारा प्राप्त होने योग्य हैं। क्षमताओं और मूल्यों के बारे में यह दृष्टि जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, उनके शिक्षा सम्बन्धि विचारों में सर्वत्र एक नयी ताजगी और स्फूर्ति होती है जो किसी भी शिक्षा व्यवस्था को बोझिल होने से बचाती है। वर्तमान परिवेश में स्वामी विवेकानन्द जी की मानव निर्माण की शिक्षा उपयोगी हो सकती है। प्रस्तुत आलेख में स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था में स्वामी विवेकानन्द जी की मानव निर्माण शिक्षा की उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है।

व्यावसायिक वरीयता के लिए व्यावसायिक निर्देशन का महत्व

सुधा

शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कोई भी कार्य व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है किंतु प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार के काम करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है प्रत्येक काम के लिए व्यक्ति को कुछ विशिष्ट प्रकार के कौशल तथा योग्यताओं की आवश्यकता होती है जो उसके व्यवसाय के दायित्व को पूरा करने के लिए अनिवार्य होती है | न्यूनतम स्तर की शिक्षा से केवल शारीरिक श्रम से संबंधित नौकरी ही प्राप्त कर सकते हैं इस स्तर पर व्यक्ति को चपरासी चौकीदार या अन्य कोई छोटी नौकरी मिल जाती है परंतु किसी व्यवसाय को करने के लिए कौशल तथा योग्यताओं की आवश्यकता होती है इन कौशलों को आंशिक रूप से अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति गीतकार का व्यवसाय सुनना चाहता है तो उसे संगीत प्रशिक्षण के अलावा गाने की स्वाभाविक योग्यता भी होनी चाहिए | व्यावसायिक मार्गदर्शन किसी व्यक्ति के व्यावसायिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है यह व्यक्ति की ताकत रुचि और कौशल और मूल्यों की पहचान करने में सहायता करता है जो उसको करियर पथ / कैरियर चुनाव करने में निर्णय लेने में सहायता करता है ताकि वह अपने कैरियर के बारे में उचित निर्णय ले सके | रोजगार बाजार में व्यावसायिक मार्गदर्शन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है वैज्ञानिक और तकनीकी युग में भौतिकवादी दृष्टिकोण को देखते हुए हमारा प्रत्येक कार्य और व्यवहार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होने वाला है? ऐसी स्थिति में समाज को प्रत्येक स्तर पर उचित रोजगार के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता है अतः प्रस्तुत शोध पत्र में व्यावसायिक वरीयता के लिए व्यावसायिक निर्देशन के महत्व पर चर्चा की गयी है |

नई शिक्षा नीति 2020

कुसुम सबलानिया

शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंज़ूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग

कु . मंजु पाण्डेय
शोधच्छात्रा, गुरुकुल कांगडी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास व प्रोत्साहन करना था| अंग्रेजी शासन की नींव समाप्त होने के तुरंत बाद भारत सरकार ने जो पहला कार्य आरंभ किया वो था देश की लचर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना , क्योंकि किसी भी देश की उन्नति का मार्ग उस देश की शिक्षा व्यवस्था ही तय करती है | स्वतंत्र भारत का शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया सबसे पहला कदम 1948 में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में गठित किया गया **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** था , तब से आद्योपांत भारत में शिक्षा को बेहतर , राष्ट्रोपयोगी व जीवनोपयोगी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए ही जा रहे हैं| **1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर** की अध्यक्षता में **माध्यमिक शिक्षा आयोग** , **1968 का कोठारी आयोग** ,इसके बाद **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** का लागू होना भारतीय शिक्षा पद्धति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था जो की लगभग 34 साल तक लगातार चली तथा वर्ष 2020 में पुनः भारत सरकार ने समय की मांग को ध्यान में रखकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक **के . कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव रखी , जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था को दिशा देती है | अभी तक हुए सभी शैक्षिक सुधारों व शिक्षा नीतियों ने प्रत्येक स्तर पर शिक्षा में तकनीकी प्रयोग का प्रबल समर्थन किया है इसी का परिणाम है की आज हमारे देश के प्रत्येक छोटे – छोटे दूरस्थ गांव तक भी बच्चों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है , आज हमारे देश के सरकारी विद्यालयों में **डिजिटल बोर्ड** की व्यवस्था है **,वर्चुवल स्कूल ,स्वयं व स्वयंप्रभा** जैसी तकनीकी के माध्यम से देश के कोने- कोने तक शिक्षा पहुँच रही है | इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्लेटफार्मों जैसे – **यू ट्यूब , अन- अकेडमी, बायजूज** जैसे अप्लिकेशन भी आज उपलब्ध हैं जो बिना किसी इंस्टीट्यूट में उपस्थिति के घर पर ही **मोबाइल फोन या लैपटॉप** के माध्यम से युवाओं को उनकी तैयारी को बेहतर करने का अवसर देते हैं ये सब शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुआ है | विभिन्न विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान भी आज अपने स्तर पर आधुनिक तकनीकि का प्रयोग कर छात्रों को उनके अध्ययन को गति प्रदान कर ने हेतु डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध करवाते हैं | सार रूप में यदि कहा जाए तो शिक्षा के बिना तकनीकि व तकनीकि के बिना शिक्षा अधूरी है शिक्षा व तकनीकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा समय- समय पर आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व प्रौद्योगिकी में अद्यतन करना आवश्यक होता है यही कार्य समय- समय पर हमारी शिक्षा नीतियाँ करती आई हैं| शिक्षा प्रौद्योगिकी शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति पहुँच व शिक्षा गुणवत्ता व जीवनोपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं जिनका उचित समाधन निकाला जाए तथा प्रौद्योगिकी तक प्रत्येक क्षेत्र व प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच सुनिश्चित की जाए तो देश की उन्नति में शिक्षा प्रौद्योगिकी का अहम् योगदान होगा |

अध्यापक और प्रौद्योगिकी

गौरव शर्मा (शोध छात्र)
शोध संस्थान- डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
gauravsharma0302@gmail.com

प्रौद्योगिकी लम्बे समय से ही नवाचार और नवाचार के परिप्रेक्ष्य में अग्रणी रहा है। हर प्रकार के प्रारूप निर्माण से लेकर इसके अद्ग्रहण तक, कोई भी यह अनुमिति नहीं कर सकता है कि प्रौद्योगिक उपकरण कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ किस प्रकार चलती है? प्रौद्योगिक उपकरणों द्वारा ही दूर देशों की प्रत्येक आवश्यक सूचना प्राप्त करना आसान बना दिया है और इसके अतिक्रित यह भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। वरन् पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए विद्वानों से विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का सपना तकनीक के कारण ही पूर्ण आकार ले पाया है। तो आइए हम प्रौद्योगिकी उपकरण के इस वैभव को कौटि-कौटि धन्यवाद ज्ञापित करें जो हमारी लागतों में कटौती करके हमारी प्रतिभाओं को प्रेरित करने की सिफारिश करते हैं।

इस लगातार बढ़ती दुनिया में, एक अनूठा ज्ञान भी आपको दूसरों से बेहतर बना सकता है। यही कारण है कि ज्ञान संबंधी सभी विकासात्मक पाठ्यक्रम अब बहुतायत में चलन में हैं। चाहे आप छात्र हों या व्यवसाय या आप नौकरी पेशेवर हों, आजकल सभी संस्थानों और कंपनियों में कुछ अलग विशेषता और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। ज्ञान और कौशल का विकासात्मक पाठ्यक्रम लेने के बाद, आप अपने क्षेत्र और व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार खुद को व्यवस्थित और व्यवस्थित कर सकते हैं।

शिक्षा में प्रबन्धन और प्रशासन की भूमिका

हरेन्द्र सिंह
शोधार्थी, उत्तर प्रदेश, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ. प्र.

शिक्षा प्रबंधन छात्रों के सीखने के माहौल को बढ़ाने के लिए सीखने की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सभी शैक्षिक प्रक्रियाओं और तकनीकों की देखरेख करता है। स्कूल सुधार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों के पास सबसे अच्छा सीखने का माहौल हो, जिसका प्रभाव लंबे समय में छात्र के प्रदर्शन और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है, हालांकि बाद में शोध विद्वानों से बहुत कम ध्यान दिया गया है। जब शिक्षा अच्छी तरह से प्रबंधित की जाती है, और देश में स्कूलों को उन्नत किया जाता है, छात्रों के प्रदर्शन में सुधार होता है, और दी जाने वाली शिक्षा प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली होती है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण भागों में उचित योजना, विद्यालय के वातावरण में सुधार, प्रभावी नेतृत्व और शिक्षक पुरस्कार और प्रशंसा शामिल हैं। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रबंधन विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्रभावी नेतृत्व और शिक्षक पुरस्कार और प्रशंसा। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रबंधन विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्रभावी नेतृत्व और शिक्षक पुरस्कार और प्रशंसा। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रबंधन विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

नई शिक्षा नीति 2020

अजय कुमार
डी.एम. कालौनी, चण्डीगढ़

राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों की सहायता करने के लिए आवश्यक सुधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य प्रांरभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, वर्तमान परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना शामिल है।

शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई के साथ साथ सह पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। इसे एक विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रत्येक स्कूल को एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है परन्तु इसके साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभावान नहीं होते है लेकिन यह धारणा गलत है। प्रत्येक माता-पिता के यह समझना होगा की सरकारी स्कूल (विद्यालयों) में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली होता है। बस जरूरत है, एक ऐसा मौका प्रदान करने की जिससे की वह अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। यदि किसी बच्चे कि रूचि चित्रकला में है तो उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल, नृत्य कला, संगीत आदि क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनमें किसी भी प्रकार की हीनभावना उत्पन्न न हो सके। यह तभी संभव है यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार स्कूल प्रबंधक माता-पिता विद्यार्थीगण मिलकर एक दुसरे के साथ शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कार्य करें।

शिक्षा नीति 2020 की समस्याएँ

शिक्षा नीति 2020 शिक्षा सबंधी असमानताओं को दूर करने का अच्छा प्रयास हे। इसमें उन विद्यार्थीयों को शामिल किया गया है जो पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करना सरल कार्य नहीं है इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं है। इन समस्याओं को दूर करना बहुत आवश्यक है।

(1) शिक्षकों की कमी
(2) माता पिता का व्यवहार (सोच)
(3) सरकारी स्कूलों (विद्यालयों) का वार्षिक परिणाम
(4) सरकारी सुविधाओं का गलत तरीके से उपयोग करना।

सरकार ने शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी विद्यालयों की स्थिति को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। वह एक ऐसी प्रणाली अपनाएं की सरकारी विद्यालयों में सह पाठयक्रम विधि से सम्बधित शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार चलती रहे। किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी न हो। इस नीति में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। अपने क्षेत्र की भाषा को बढ़ावा देना एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है लेकिन क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने से बच्चे को भविष्य में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई करने के पश्चात व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही नौकरी या अन्य व्यापारिक गतिविधियां कर सकता है। यदि वह दुसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसे भाषा सम्बधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इन समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है।

निष्कर्ष: नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधारवादी नीति बन सकती है। हम सभी को मिलकर इस नीति को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

बिहार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्या और समाधान

अर्चिता कुमारी

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया

Email:- architakri1993@gmail.com

बिहार में शिक्षा की प्रणाली परीक्षा केंद्रित के बजाय सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों को सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो जनता को आकर्षित करे, इसलिए छात्र को हमेशा इस तरीके से सीखने का मौका नहीं मिलता है कि वे सबसे अच्छे से पहचान करते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे अपनाना।

प्राथमिक शिक्षा में समस्या

1. वर्ग का आकार :- बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं, जिनके भवन नहीं हैं। उनमें से कुछ बरगद के पेड़। अगर किसी स्कूल में भवन हैं तो बैठने के लिए बेंच नहीं है। छात्र बोरी के साथ फर्श पर बैठने और अध्ययन करने के लिए आते हैं।

2. शिक्षण पद्धति:- शिक्षक योग्य भी नहीं हैं, हालांकि महिला शिक्षकों को वहाँ छात्र को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ शिक्षक छात्रों को घर का काम करने के लिए कहते हैं जैसे कि सब्जियां काटना।

3. वित्तीय बजट:- बजट आवंटन काफी अच्छा है लेकिन प्राथमिक शिक्षा प्रणाली और छात्रों के सीखने के अनुभव की गुणवत्ता में। बजट में कटौती का प्रभाव स्कूल क्या सीखने के उपकरण संसाधन फर्नीचर पर पैसा खर्च करने का प्रयास कर सकता है।

4. सुधार :- भारत में शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा केंद्रित होने के बजाय सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5. नई शिक्षण पद्धति:- शिक्षक कुशल होना चाहिए और विभिन्न शिक्षण विधियों से अवगत होना चाहिए जो दृश्य, श्रवण और किनेस्थेटिक के रूप में वर्गीकृत हैं। प्रत्येक छात्र के पास सीखने की अपनी क्षमता होती है।

6. वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं:- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अपनी स्वयं की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए ताकि छात्र को अनुसंधान विधियों का वास्तविक तरीका पता हो।

भौतिक जीवन की सफलता में मूल्य शिक्षा की उपयोगिता

धीरज कुमार वर्मा
राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ,अयोध्या (उत्तर प्रदेश)
E mail :- dhirajve425@gmail.com

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका सामाजीकरण समाज के विश्वासों आदर्शों और सिद्धान्तों और सामाजिक मानदण्डों से निर्धारित होता है ।समाजीकरण की प्रक्रिया ही उसे अन्य जीवों से पृथक करती है। समाज के नियम आदर्श अथवा मानदण्ड जब व्यक्ति अंतः करण से अथवा विश्वास के रूप में स्वीकार करता है, तो इन्हें मूल्य की संज्ञा दी जाती है। मूल्यपरक शिक्षा आवश्यक क्यों है, इसका मूल कारण है आज की भौतिक समृद्धि। इसी भौतिक समृद्धि को ही आज सुख-दुख, मान सम्मान का आधार माना जाता है। यही कारण है कि आज व्यक्ति भौतिक समृद्धि के लिए उस पद को प्राप्त करना चाहता है जिसके कि वह योग्य नहीं है, चाहे व्यक्ति को किन्ही भी मूल्यों के साथ समझौता क्यों ना करना पड़े।

मूल्य की अवधारणा मनुष्य के प्रत्येक चुनाव, निश्चय ,निर्णय तथा कार्य में विद्यमान होती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में किसी व्यक्ति ,वस्तु आदि के बारे में विभिन्न उद्देश्यों को आधार मानकर निर्णय लेता है कि क्या सही है, क्या गलत ,इन्हीं निर्णय में व्यक्ति के मूल्य की अवधारणा छिपी होती है।

आधुनिक सन्दर्भ में आचार्य विनोबा भावे के शैक्षणिक विचारों की प्रासंगिकता

अभिषेक कुमार
शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

शिक्षा को व्यापक अर्थ में स्वीकार करते हुए आचार्य विनोबा भावे ने आंतरिक एंव ब्राह्य शिक्षा के दो रूपों का वर्णन किया है, तथा सम्पूर्ण शिक्षा को सीखने की प्रकिया से जोड़ कर देखा हैं। उन की दृष्टि में सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हैं जो जीवन पर्यन्त चलती रहती हैं। वही दूसरी और मानवीय मूल्यों का महत्व समझते हुए विनोबा जी ने स्पष्टरूप से आत्मशक्ति को शिक्षा के माध्यम से पहचाननें तथा कर्म योग की शिक्षा पर जोर दिया हैं। सर्वोदय दर्शन को जीवन का सच्चा दर्शन मानते हुए विनोबा जी ने देश के लिए आत्मसंयमी, विनयी, आत्मनिर्भर, समाजसेवी और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनना सम्पूर्ण शिक्षा का प्रमुख उद्धेश्य बताया हैं। इसलिए विनोबा जी के शिक्षा के उद्धेश्य आधुनिक समय में भी उनके शैक्षिक सर्वोदय समाज के लक्ष्य के अनुरूप हैं। आधुनिक शिक्षा के सम्बन्ध में उनका यह मत कि-"नई तालीम एक पद्धति नहीं बल्कि जीवन विचार हैं" एक सकारात्मक प्रासंगिकता प्रकट करता हैं। इसलिये आधुनिक सन्दर्भ में आचार्य विनोबा भावे के शैक्षणिक विचारों का मूंल्याकन करना इस शोध पत्र का प्रमुख विषय हैं। क्योंकि भूमण्डलीकरण के इस दौर में भी विनोबा जी की शिक्षा योजना उन सभी नए मूल्यों से परिपूर्ण हैं जिन की आज समाज को सबसे अधिक आवश्यकता हैं।

इस प्रकार शोधकर्ता प्रस्तावित पत्र में आधुनिक सन्दर्भ में आचार्य विनोबा भावे के शैक्षणिक विचारों की प्रासंगिकता को सकारात्मक रूप से व्याख्यायित किया गया हैं।

समकालीन शिक्षा तंत्र में मातहत समाज: एक व्यष्टि अध्ययन

शैलेश

समाजकार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110007

इस लेख में उपयुक्त मातहत समाज वर्तमान के बहुजन समाज से भिन्न है। जो अंतनिओ ग्रामसी द्वारा सृजित हुआ है। मातहत समाज उन सामाजिक, आर्थिक और राज-नैतिक लोगों का समूह है जो लंबे समय से देश की सत्ता से दूर रहे। और विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे। बहुजन शब्द का अभिपर्याय देश की पिछड़ी और दलित जातियों से हैं| जिनका सामाजिक सरोकार भारत के विभिन्न धर्मों से है।अतीत के अनुभव इसके द्योतक हैं कि बहुजन समाज का सृजन राजनैतिक बदलाव के लिए हुआ। जहां राजनीति के माध्यम सामाजिक बदलाव की बात होती है। मातहत समाज के सिद्धान्त की बात करें तो सामाजिक बदलाव इसकी जड़ में हैं। सामाजिक बदलाव में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता अहम रोल निभाती है। इस प्रकार से शिक्षा एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारक है। ये शोध पत्र भारत की तत्कालीन शिक्षा तंत्र संभावनाएं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालने का काम कर रहा है।

ये शोध पत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बुलंदशहर जनपद से संबन्धित है। बुलंदशहर की फ़तेहपुर, हरिद्वारपुर, और भोपतपुर पंचायत इस शोध अध्ययन की केंद्र में हैं। यह शोध पत्र अपने उद्देश्य से संबन्धित सूचना इकट्ठा करने के लिए प्रशनावली अनुसुचि का प्रयोग करता है। और आजादी के लगभग सत्तर साल बाद भी शिक्षा में सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है? क्या सामाजिक न्याय ने उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया है जिनकों निर्धारित किया गया था? अगर लक्ष्य पूरा नहीं हो पाए तो सामाजिक न्याय की विफलता के क्या कारण हैं? भविष्य में सामाजिक उत्थान व सशक्तिकरण की क्या सम्भावनाएं हैं? और स्थानीय स्तर पर इन शिक्षण संस्थानों पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं का क्या प्रभाव है? ये शोध-पत्र इन्ही प्रश्नों के उत्तर को टटोलनी की एक पहल है।

मुख्य-शब्द: मातहत समाज, शिक्षण संस्थान, स्थानीय लोकतान्त्रिक संस्थान , सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान, सशक्तिकरण

स्त्री हि ब्रह्मा बभूविय

प्रकृति
कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

वस्तुतः वेदों के द्वारा ही प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के सदृश अन्य वस्तु अप्राप्य है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है।

।। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।।

गीता 4 अ0.

यद्यपि मेरे शोधपत्र का विषय ''स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ'' है, इसलिए सार के रूप में नारी की स्थिति को जान लेना उचित होगा। नारियों को वेदाध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों की रचना कवित्रियों ने की है। रोमशा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता, घोषा, लोपामुद्रा आदि पण्डिता नारियाँ इनमें सर्वप्रसिद्ध हैं। राम के युवराज पदं पर अभिषेक के समय कौशल्या ने यज्ञ सम्पादित किया था। सुग्रीव की पत्नी तारा ने भी सुग्रीव के युद्ध में विजय के लिये यज्ञ सम्पादित किया था। इन दोनों स्त्रियों को मन्त्रविद कहा जाता है। पाण्डवों की जननी कुन्ती अथर्ववेद की पण्डिता थी। वेद में स्त्री के लिए अनेक स्थलों पर पुरंधि इस शब्द का प्रयोग मिलता है। जिनका शब्दार्थ है – ''पुरं नगरं दधातीति पुरंधिः'' अर्थात् जो नगर की रक्षा और पोषण करें।

मनु ने स्त्री को राज्य–संचालन के योग्य माना है, उनका कहना था कि राजा की स्वजातीय, गुह्य लक्षणों वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हृदयप्रिय तथा रुप–गुण युक्त राजमहिषी परिस्थिति आने पर राज्य कार्य का संचालन भी कर सकती थी। कवियों की दृष्टि में नारी माया सी दुर्बोध, प्रकृति–सी बहुरुपी साथ ही सहानुभूति सी सरल रही है। एक स्थान पर तो ब्रह्मरुप में नारी ही है। हे देव! तू ही पुरूष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है।

।। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी।।

श्वेता0. 4/5

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री, माता, पुत्री, भगिनी और पत्नी होने के साथ–साथ वह एक विदुषी स्त्री का भी रूप रखती है जिसको ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आगे शोधपत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है।

बिहार माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रशासन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका

ज्योति कूमारी

शोधार्थी, लोक प्रषासन विभाग, म0, वि0, वि0, बोधगया

E-mail : sweetjyoti2793@gmail.com

प्रस्ताविक अध्ययन ''बिहार माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रषासन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका'' का एक अध्ययन है। आज शिक्षा का उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यापक एवं व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकता होती है, ताकि शिक्षा के प्रशासन में सुशासन के गुण स्थापित कि जा सकें। भारत में प्राचीन काल से ही सुशासन की धारणा आध्यात्मिकता के आधार पर रही थी। वर्तमान में सरकार और शासन पर काफी चर्चाएं हो रही है। यद्यपि इन्हें एक दूसरे का पर्याय समझा जाता है। किन्तु सच्चे अर्थ में ऐसा इसलिए नहीं होता कि शासन, सरकार शब्द से व्यापक अर्थों में है। सरकार–तंत्र एवं संस्थागत व्यवस्थाओं के द्वारा सम्पादित सम्प्रभु शक्तियाँ, जिसका प्रयोग आंतरिक एवं बाह्य रूप से राजनीतिक समूह के हित में किया जाता है, जबकि शासन का अर्थ समाज की भलाई के लिए लिया गया आधारिक निर्णय, जिसमें प्रक्रिया एवं परिणाम संबंधित होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था निर्णय लेने की प्रक्रिया को इंगित करता है और इन प्रक्रियाओं का भी वर्णन करता है कि इसे कैसे लागू किया जाय? या नहीं किया जाएं। प्रशासनिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा स्थानीय स्तर पर भी लागू है।

शैक्षिक प्रशासन की सामाजिक एवं आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत नेतृत्व व्यवहार प्रशासनिक व्यवहार और निर्णय लेना इसकी मुख्य आधारशिला है। जिसके द्वारा सुशासन के सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। वहीं अगर बिहार में सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षिक प्रशासन में सुशासन व्यवस्था की बात की जाए तो, हम पाते हैं कि निम्न उत्पादकता एवं कार्यत कर्मचारी असंतोष एवं संघर्ष सूचना विस्फोट अथवा नवीन वातावरणीय चुनौतियां में प्रशासकों को चिंता में रखती है कि वह किस प्रकार शैक्षणिक व्यवस्था ने नेतृत्व व्यवहार प्रशासनिक व्यवहार तथा निर्णय शक्ति इत्यादि को किस प्रकार सुनिश्चित करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा से जुड़े अन्य समग्र एक चिंतनीय विषय है। जहां पर सुशासन व्यवस्था पूर्णता लक्ष्य पर आधारित होती है। वही कई ऐसी नीतियां भी सामने प्रकट आती है कि, इसकी संचालन किस प्रकार की जाए।

सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुसार प्राथमिक स्तर में आने वाली बाधाओं का निवारण

मनीषा सिंघल

शोधार्थी, महर्षि युनिवर्सिटी ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ

शिक्षा मानव विकास का मूल सारांश है इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। नवजात शिशु असहाय अवस्था में जन्म लेता है। शिशु बोलना, चलना, फिरना कुछ नहीं जानता। सांसरिक भेदभाव से रहित कोमल शिशु का कोई शत्रु अथवा मित्र नही होता है सामाजिक परम्पराओं, समस्याओं रस्मों का ज्ञान उसको नहीं होता और न ही किसी आदर्श अथवा नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। शिशु की आयु बढ़ाने के साथ–साथ उसमें शारीरिक, मानसिक संवगे ात्मक परिवर्तन आते जाते हैं तथा इसके साथ ही उसमे ं सामाजिक परिवर्तन आते जाते हैं तथा इसके साथ ही उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। हमारे भारत में आज प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, इसमें क्या दोष आ गये हैं, सरकार की आरे स` इसमें गुणात्मक सुधार हेतु क्या–क्या योजनाएँ चलाई जा रही हैं, विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की क्या उपलब्धता है कक्षा शिक्षण अधिगम में क्या गुणात्मकता की क्या उपलब्धता है कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम में क्या गुणात्मकता लाई जा सकती है। प्रस्तुत शोध आलेखों में शोधर्थियों ने इन्हीं प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की है। शिक्षा मे ं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझावों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता

राजीव कुमार
शोधार्थी, एन. ए. एस. कॉलेज, मेरठ, उ. प्र.

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था जानने के लिए नवम्बर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के रुप में अध्यक्ष डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया । इन्ही के नाम पर इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। अगस्त 1949 में इस आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

वर्तमान समय में भी इस आयोग के सुझाव अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव आयोग ने दिया था। आज भी उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में ही है।

इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करने का सुझाव दिया था जिसके कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ जो आज भी विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालयो को आवश्यकतानुसार अनुदान देता आ रहा है। जिससे उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है।

परीक्षा दिवसों को छोड़कर 180 कार्यदिवस निश्चित करना भी इस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी । इससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयो पर अंकुश लगा हुआ है और उच्च शिक्षा के सुचारू रूप से चलने में मदद मिल रही है।

विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक एवम तकनीकी शिक्षा जो आज दी जा रही हैं वे सब इसी आयोग की देन हैं। सभी क्षेत्रों में शोध को आज भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

शिक्षको के वेतनमान और सेवाशर्तो में सुधार का सुझाव भी आज के समय में उच्च शिक्षा के लिए लाभदाई सिद्ध हो रहा है। शिक्षक आज शिक्षण और शोध कार्यों में बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं जिससे उच्च शिक्षा की दिशा और दशा में अपेक्षित सुधार हो पा रहे हैं।

स्पष्ट हो गया है कि विश्वविद्याय शिक्षा आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव आज भी उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे।

"जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र निर्माण कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वहीं वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है।"

–स्वामी विवेकानन्द

नई दुनिया के निर्माण के
लिए शिक्षा भी नए प्रकार की होनी चाहिए।

–महात्मा गाँधी

Website:- www.guhar.org/
Facebook:- www.facebook.com/guhar.org
Youtube:- www.youtube.com/@guharngo